শর্মা হার্ডওয়্যার
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित
राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 10 | अंक : 341 | गुवाहाटी | गुरुवार, 11 जुलाई, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

डेंगू की रोकथाम के प्रबंधन की तैयारियों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा पेज 2
एपीसीसी की अनुशासन समिति की पहली बैठक आयोजित पेज 3
गहलोत के 25 लाख के फ्री इलाज को टक्कर देने के लिए भजनलाल ने खेला बड़ा दांव पेज 5
मदेवदेव ने सिनर से बदला लिया, पाओलिनी ने इटली के लिए रचा इतिहास पेज 7

कॉलेज के प्रिंसिपल नगरपालिका कर संग्राहक नहीं हैं : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज कालेजों में शुल्क माफी के पहले चरण के भुगतान के रूप में 349 शैक्षणिक संस्थानों को 68.44 करोड़ रुपए वितरित किए। इस पहल से लगभग 1 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने राज्य के कॉलेजों के प्राचार्यों पर तंज कसते हुए कहा कि कॉलेजों के प्रिंसिपल कोई नगर निगम के टैक्स संग्राहक नहीं हैं। बुधवार को गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में आयोजित प्रज्ञान भारती योजना के तहत राशि वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश को पूरी तरह से मुफ्त करने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने प्रिंसिपलों को मैगजीन और कॉलेज वीक के नाम पर छात्रों से 600-600 रुपए वसूलने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में छात्रों का प्रवेश नि:शुल्क होना चाहिए। कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के समय लिये जाने वाले 600 रुपए का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज के प्राचार्यों से मेरा अनुरोध है कि कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश मिलता है। उसके बाद भी छात्रों से वसूली नहीं करते रहें। छात्रों से 600 रुपए क्यों लें? जरूरत पड़े तो मुझसे वह 600 रुपए मांग लीजिए। उन्होंने दोहराया कि छात्रों के प्रवेश के लिए सभी व्यवस्थाएं नि:शुल्क करें। यदि आवश्यक हो तो यह नहीं कहा जाना चाहिए कि सरकार ने उनके प्रवेश को मुफ्त कर दिया है, बल्कि यह कहें कि यह व्यवस्था प्रिंसिपल ने की है। तभी प्रिंसिपल और छात्र के बीच संबंध सुधरेंगे। लेकिन, आप उन पर 600 रुपए -शेष पृष्ठ दो पर

एआई और प्रौद्योगिकी का उपयोग अपरिहार्य है : सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कॉलेज प्रवेश को सुव्यवस्थित करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है, और कहा है कि प्रौद्योगिकी एकीकरण अपरिहार्य है और भविष्य के शासन के लिए महत्वपूर्ण है। शर्मा ने कहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन तकनीक बनी रहेगी। उन्होंने एआई के मौजूदा और भविष्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रक्रियाओं को अधिक सुचारू और अधिक कुशल बनाने के लिए तकनीक का कार्यान्वयन आवश्यक है। समर्थ पोर्टल की प्रभावशीलता के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, शर्मा ने कहा कि यदि हमें कोई समस्या आती है, तो हम उन्हें अपनी तकनीकी टीम को बताएंगे और समाधान के लिए उन्हें दिल्ली स्थित एक टीम के पास भेजेंगे। यह पोर्टल हमारे द्वारा विकसित नहीं किया गया है, लेकिन हम किसी भी समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय संस्थाएं, जैसे समाचार पत्र और शैक्षणिक संस्थान, एआई क्रांति में बाधा नहीं डाल सकते। भविष्य एआई और प्रौद्योगिकी का है। हम प्रतिदिन या अमर असोम जैसे प्रकाशनों के माध्यम से एआई को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं एआई पर निर्भर हैं। शर्मा ने चैटजीपीटी जैसी तकनीकी प्रगति को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और उनके लाभों और कमियों के बारे में बौद्धिक चर्चाओं को प्रोत्साहित किया। हमें तकनीकी क्रांतियों का स्वागत करना चाहिए जो छात्रों को किसी भी चुनौती का समाधान करने के लिए सूचित और सामूहिक प्रयासों से लाभान्वित करती हैं। असम के प्रवेश पोर्टल की सफलता पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार और गोवा के शिक्षा मंत्रियों ने हमारी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए असम का दौरा किया। यह उपलब्धि हमारे -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य कैबिनेट ने दत्तक ग्रहण देखभाल अवकाश को मंजूरी दी

गुवाहाटी। असम मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक निर्णयों की श्रृंखला में राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। एक प्रगतिशील कदम के तहत, असम सरकार ने एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 180 दिनों की *दत्तक ग्रहण देखभाल छुट्टी* को मंजूरी दे दी है। यह पहल केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 43-बी के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि गोद लिए गए बच्चों को उचित देखभाल और पोषण मिले। इस निर्णय से कई महिला कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है, जिससे उन्हें काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने सरकारी सेवा क्षेत्र में जनशक्ति के बेहतर उपयोग के लिए असम राज्य कृषि विपणन -शेष पृष्ठ दो पर

ड्रैगन ने फिर से अरुणाचल पर किए खोखले दावे

बीजिंग। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत को उस क्षेत्र में विकास कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है। एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही गई जिसमें सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने की भारत की योजना के बारे में बताया गया। सूत्र ने मंगलवार को बताया कि भारत पूर्वोत्तर हिमालयी राज्य में 12 जलविद्युत स्टेशनों के -शेष पृष्ठ दो पर

एचआईवी से छात्रों की मौत : मचा हड़कंप सरकार ने खबर को बताया भ्रामक

अगरतला। त्रिपुरा सरकार ने बुधवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें उस रिपोर्ट को *भ्रामक* बताया गया जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में 828 छात्र एचआईवी के रूप में पंजीकृत हैं। सरकार ने कहा कि ये आंकड़े अप्रैल 2007 से मई 2024 तक के संचयी हैं। रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, त्रिपुरा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्स पर एक संदेश में कहा कि यह बताया गया है कि, त्रिपुरा में 828 छात्र एचआईवी पॉजिटिव के रूप में पंजीकृत हैं, और उनमें -शेष पृष्ठ दो पर

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं हैं, जितना की सीखने की इच्छा न रखना।

-अज्ञात

उपचुनाव : प. बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा

कोलकाता (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में बुधवार को चार विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। हालांकि यह शांतिपूर्वक नहीं रह गया है। अलग-अलग इलाकों से हिंसा और चुनाव में गड़बड़ी की कई घटनाएं सामने आईं हैं। हिंसा की शिकायतें मुख्य रूप से नदिया जिले के राणाघाट-दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर 24 परगना के बागदा से सामने आईं हैं। रायगंज में भी मतदान शांतिपूर्वक नहीं रह गया है। सुबह 11 बजे तक पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में चुनाव में गड़बड़ी की 26 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें -शेष पृष्ठ दो पर

पीएम मोदी और आस्ट्रियाई चांसलर के बीच विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के बीच बुधवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इसमें द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वार्ता के दौरान व्यापार और निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, एआई, स्टार्ट-अप, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक सहयोग और लोगों से लोगों के बीच संबंध से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। इससे पहले द्विपक्षीय संबंधों में नया इतिहास रखते हुए प्रधानमंत्री का आस्ट्रिया के चांसलर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। संघीय चासंलर परिसर में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर में अब शांति हैं : सीएम

नई दिल्ली। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दावा किया कि राज्य में कई दिनों से शांति बहाल है। उन्होंने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राज्य में शांति स्थापित करने का संकल्प लिया है। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि हमने एक संकल्प लिया है। मणिपुर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में जो कुछ भी किया जा रहा है, उसकी समीक्षा करने और जल्द ही शांति लाने का संकल्प हमने लिया है। यहां कई दिनों से शांति है। प्रधानमंत्री के मणिपुर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पीएम के आने या न आने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

न्यूज गैलरी

दिल्ली में कंपनियों ने बिजली दरें बढ़ाई

नई दिल्ली। दिल्ली में 1 मई से बिजली के बिल बढ़ गए हैं। बिजली कंपनियों ने बिजली के दाम बढ़ा दिए है, जिसके बाद अब लोगों की जेब से बिजली का बिल भरने के लिए अधिक राशि खर्च होगी। घर और व्यवसायों के लिए बिजली का बिल अधिक होगा। वहीं जुलाई में निवासियों -शेष पृष्ठ दो पर

भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस में गडकरी ने कहा-

सामूहिक शक्ति से बनाएंगे भारत को महान

नई दिल्ली (हि.स.)। भारत विकास परिषद ने बुधवार को अपना 62वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रहे। इसके साथ भारत विकास परिषद् के संस्थापक (स्व.) डॉ सूरज प्रकाश के जन्मदिवस (27 जून) से शुरू किए गए सेवा पखवाड़े का भी समापन हुआ। नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित स्थापना दिवस और सेवा पखवाड़ा समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स का महत्व बताते हुए कहा कि किस तरह शुरुआत से सामाजिक मानवीय शोषण की प्रथा का भारत में अंत हुआ। भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए गडकरी ने कहा -शेष पृष्ठ दो पर

जम्मू-कश्मीर से अवैध विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने के लिए बनाया गया पैनल

श्रीनगर। पिछले 13 वर्षों से जम्मू-कश्मीर में रहने वाले अवैध विदेशियों की पहचान करने के लिए यूटी प्रशासन ने सात सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल उन अवैध विदेशियों की पहचान करेगा जो 2011 से अधिक समय से रह रहे हैं और उनके निर्वासन की सुविधा प्रदान करेगा। सात सदस्यीय पैनल को अवैध प्रवासियों की जीवनी और बायोमेट्रिक -शेष पृष्ठ दो पर

असम सरकार
क्या कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपसे रिश्वत मांग रहा है ?
कृपया हमें सूचित करें
व्हाट्सएप नम्बर 60269 01243
टोल फ्री नम्बर 18003453767
नियंत्रण कक्ष 03612462295
एस.पी (I) 6026903481
एस.पी (II) 6026903483
एडिशनल एस.पी 6026903418
ईमेल complaints.vac@gmail.com
ट्विटर @DIR_VAC_ASSAM
सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय, असम गुवाहाटी ७८१०३२
https://dgvigilance.assam.gov.in/
--Janasanyog/D/2356/24/11-Jul-24

अमेरिका ने भी माना : भारत ही रुकवा सकता है रूस-यूक्रेन जंग

वॉशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफल रूस दौरा संपन्न हो गया। पीएम मोदी के रूस दौरे पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर थी। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की गहरी दोस्ती साफ नजर आई। ऐसे में अमेरिका भी मोदी और पुतिन की दोस्ती का लोहा मानने लगा है। अमेरिका को भी यकीन है कि केवल भारत ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मना सकता है। अमेरिका ने कहा है कि रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। इसी रिश्ते की वजह से भारत के पास रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को कहने की क्षमता है। रूस-यूक्रेन -शेष पृष्ठ दो पर

रूसी सेना में कार्यरत भारतीयों की होगी स्वदेश वापसी

मास्को (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद रूसी सेना में कार्यरत भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वेदश वापसी का रास्ता खुलने के साथ ही उनकी भर्ती बंद करने पर मास्को तैयार हो गया है। भारत की मांग पर रूस ने सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अनौपचारिक मुलाकात के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements à¿lease contact
97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc.
ARTCLE WORLD, S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01,
Ph. : 94350-48866, 94018-06952

डेंगू की रोकथाम के प्रबंधन की तैयारियों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा

नई दिल्ली (हि.स.)। मानसून में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के मद्देनजर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री को देश भर में डेंगू की स्थिति की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि केंद्रित, समयबद्ध और सहयोगात्मक गतिविधियों के परिणामस्वरूप डेंगू मामले की मृत्यु दर 3.3 प्रतिशत (1996) से घटकर 2024 में 0.1 प्रतिशत हो गई है। मानसून की शुरुआत से उत्पन्न चुनौती और बरसात के मौसम के दौरान डेंगू के मामलों की बढ़ती संख्या के खतरे को

रेखांकित करते हुए जे पी नड्डा ने डेंगू के खिलाफ तैयार रहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू के खिलाफ रोकथाम और प्रबंधन उपायों को मजबूत करने का निर्देश दिया। जेपी नड्डा ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे मुख्य रूप से उच्च बोझ वाले राज्यों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें, जहां अक्सर प्रकोप की सूचना मिलती है। उन्होंने अधिकारियों से डेंगू की रोकथाम पर ठोस परिणाम लाने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), शिक्षा मंत्रालय और नगर निगमों और स्थानीय स्वशासन को शामिल करते हुए अंतर-मंत्रालयी अभिसरण बैठक पर जोर दिया। अधिकारियो को 24/7 केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही राज्यों को समान सहायता के लिए हेल्प लाइन नंबर चालू करने की सलाह दी गई। अस्पतालों को समर्पित डेंगू वार्ड के साथ पूरी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी और दवाओं को सुनिश्चित करने को कहा।

प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दस की मौत

प्रतापगढ़ (हि.स.)। प्रतापगढ़ में बुधवार को देर शाम अलग-अलग थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से पति-पत्नी समेत 10 लोगों की मौत हो गई। इस प्राकृतिक आपदा से जनहानि की सूचना पर राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी का शव पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही हर संभव आर्थिक सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। आकाशीय बिजली गिरने से जिले में अलग-अलग थाना क्षेत्र में 10 लोगों की मौत हो गई। इससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मृतकों के घर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया है। बुधवार की शाम हल्की बारिश के समय तेज बादल की कड़कड़ाहट के बीच आकाशीय बिजली गिरने का दौर शुरू हुआ। यहां कंधई थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में धान के फसल की रोपाई कर रहे किसान अर्जुन (45) उसकी पत्नी सुमन (42), कंधई के अमहरा गांव की राम प्यारी (48) की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। अंतू थाना क्षेत्र के पारा हमीरपुर नीम डबहा गांव के पास बकरी चरा रहे विजय कुमार वर्मा (40) भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया, इससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। जेठवारा थाना क्षेत्र के तिलहर डेरवा गांव के पास रहने वाले चंद्रशेखर की पत्नी आराधना (50) आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई।

CONSULTATION WITH
APOLLO HOSPITALS, CHENNAI EXPERTS
Will be available only for consultation at Guwahati on 14-07-2024
Gastro Clinic
Dr M. Preethi MBBS, DNB (Med), MRCP, DM (Gastro)
Patients suffering from Jaundice,Ulcers,Gallbladder Stone, Blood in motion, Abdominal Pain, Acidity, Anorectal disease (Pile & Fistula), Liver Cirrhosis, Alcoholic Liver disease, Fatty Liver disease, Hepatitis B & C, Pancreas & Bladder cancers, Gastroesophageal Reflux disease, Esophageal cancers, Burning Sensation in the stomach, Change in Bowel Habits, Acute & Chronic Pancreas disease etc.
APOLLO HOSPITALS REGIONAL OFFICE
Rajgarh Main Road, Opp-By Lane -10
Ph : 8404037649, 0361-3102166, 0361-3102669

APOLLO HOSPITALS CHENNAI
NEUROLOGIST
DR. SRIKANTH SRINIVASAN MD, DMMast of Psychiatry (Melbourne)
Will be available only for consultation at Guwahati
ON 20th July'2024
Patients suffering from fits, headache, paralysis, Epilepsy, chronic pains, slowness of movements, involuntary movement of body, face, neck , instability, giddiness, sleep disorders, poor memory, tiredness, back & neck pain, loss of consciousness, etc can register their names:
APOLLO HOSPITALS REGIONAL OFFICE
Rajgarh Main Road, Opp-By Lane
Ph :8404037649, 03613102669, 0361-3102166

आप्रेशन स्माइल के तहत पांच बच्चों को किया रेस्क्यू

फरीदाबाद (हिंस)। *आप्रेशन स्माइल* के तहत अपराध शाखा कैट की टीम ने भीख मांगने वाले पांच बच्चों का रेस्क्यू कर उनके जीवन को सही दिशा दिखाने का कार्य किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि *आप्रेशन स्माइल* के तहत कार्य करते हुए अपराध शाखा कैट ने एत्मादपुर गांव के पास से पांच नाबालिक बच्चों को भीख मांगते हुए रेस्क्यू किया है। सभी बच्चों की उम्र 7 से 13 वर्ष के बीच है। भीख मांगने वाले नाबालिग बच्चों व उनके अभिभावकों की काउंसलिंग कराई गई। चेयरपर्सन बाल कल्याण समिति फरीदाबाद ने उपरोक्त बच्चों के परिजनों को हिदायत देकर बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि स्कूली शिक्षा मानवीय समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विज्ञता मुंदड़ा को मिली सीसीआरटी छात्रवृत्ति

होजाई (निसं)। विज्ञता मुंदड़ा को सीसीआरटी छात्रवृत्ति मिली है। उसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान, संस्कृति और संसाधन प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) की संस्कृति प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना 2024-2025 में *सत्रिया नृत्य* में जूनियर छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। वह गुवाहाटी निवासी रामावतार-बिमला मुंदड़ा की पोती और आदित्य-शिल्पा मुंदड़ा की बेटी हैं।

वह गुवाहाटी के खानापारा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा हैं। उल्लेखनीय है कि वह वर्ष 2020 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की प्राप्तकर्ता श्रीमती जॉलीमोनी सैकिया के मार्गदर्शन में *संस्कृति* नामक संस्था में सत्रिया नृत्य का प्रशिक्षण ले रही हैं। उसके परिवार के सदस्य और शुभचिंतक ने उसकी इस उपलब्धि पर खुश व्यक्त की है। उन्होंने शास्त्रीय भारतीय नृत्य के क्षेत्र में उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

भाजपा की शिक्षा विरोधी नीयत के कारण मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में : राहुल

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के छात्रों के प्लेसमेंट और वार्षिक पैकेज में कथित तौर पर गिरावट को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शिक्षा विरोधी नीयत के कारण मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष अपनी पूरी शक्ति से युवाओं की आवाज निरंतर उठाता रहेगा और इस अन्याय पर सरकार को जवाबदेह बनाकर रहेगा। राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक खबर साझा करते हुए कहा कि आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव अब देश के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी झेल रहे हैं। आईआईटी में प्लेसमेंट और वार्षिक पैकेज में गिरावट, बेरोजगारी का चरम झेल रहे युवाओं की स्थिति पर और गहरा आघात कर रहे हैं। 2022 में 19 प्रतिशत छात्रों को कैम्पस प्लेसमेंट नहीं मिल सका और इस वर्ष वही दर बढ़कर दोगुनी, यानी 38 प्रतिशत हो गई। उनका कहना है कि जब देश के सबसे प्रसिद्ध एवं सम्मानित शिक्षा संस्थानों का यह हाल है तो बाकी संस्थानों की क्या दुर्गति होगी? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि आज युवा बेरोजगारी से पूरी तरह टूट चुका है - पेशेवर शिक्षा पाने में माता-पिता लाखों खर्च कर रहे हैं, विद्यार्थी ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज ले कर पढ़ने पर मजबूर हैं। फिर नौकरी न मिलना, या साधारण आमदनी उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट ही पैदा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा की शिक्षा विरोधी नीयत का ही नतीजा है जो इस देश के मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या मोदी सरकार के पास भारत के मेहनती युवाओं को इस संकट से मुक्ति दिलाने की कोई योजना भी है? उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी पूरी शक्ति से युवाओं की आवाज निरंतर उठाता रहेगा, इस अन्याय पर सरकार को जवाबदेह बनाकर रहेगा।

पृष्ठ एक का शेष

कॉलेज के प्रिंसिपल...

का बोझ डालते हैं ताकि पत्रिकाएं निकाल सकें और कॉलेज वीक सेट कर सकें। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूब बंशर कॉलेज के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। अन्य कॉलेजों के प्रिंसिपलों को समझाने की जरूरत नहीं है। क्या मेरे पास कॉलेज के प्रिंसिपल को समझाने की हिम्मत है? मैं नियमों को लागू करता हूं। मुझे समझाने का अधिकार नहीं है। अगर मैं समझाऊं तो वह क्यों समझेंगे। न तो समझाना हमारा काम है और न ही समझना आपका काम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानाचार्यों के भाई-भतीजावाद से सरकार को परेशानी होती है। उन्होंने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि वे छात्रों से लिये गए 600 रुपए वापस कर दें। हम 30 सितंबर तक आपको मुफ्त प्रवेश की संपूर्ण राशि जारी करेंगे। छात्रों से किसी भी कारण से पैसे न लें। उन्होंने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि वे छात्रों से सरस्वती पूजा शुल्क भी नहीं वसूलें।

एआई और प्रौद्योगिकी ...

लिए गर्व की बात है, लेकिन हमें भ्रम से बचना चाहिए और आगे के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने शिक्षा में एआई के भविष्य के बारे में आशा व्यक्त की और हितधारकों से सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा छात्रों के लाभ के लिए सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी मुद्दे का सहयोगात्मक रूप से समाधान करने का आग्रह किया।

राज्य कैबिनेट ने ...

बोर्ड (एएसएएमबी) के कर्मचारियों के लिए वित्तीय निपटान योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, एएसएएमबी के 612 नियमित कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश की जाएगी। इसके अतिरिक्त, एएसएएमबी के 147 आकस्मिक/निश्चित वेतन कर्मचारियों को एकमुश्त निपटान/ग्रेच्युटी भुगतान प्रदान किया जाएगा, जिसमें निपटान पैकेज में अतिरिक्त 10 प्रतिशत सद्भावना राशि जोड़ी जाएगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके सपनों का घर बनाने या खरीदने में सहायता करने के लिए, कैबिनेट ने अपॉन घर योजना को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत ऋण सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी, जिसमें 1त्न ब्याज छूट भी शामिल है। अब तक इस योजना के तहत ब्याज छूट के रूप में 596 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे 37,277 राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिला है। राज्य के भीतर व्यापारिक वस्तुओं की सुगम आवाजाही को सुगम बनाने के लिए, विशेष रूप से ई-कॉमर्स के युग में, मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों में व्यापारिक वस्तुओं के असम परिवहन योजना, 2024 को मंजूरी दे दी है। असम मोटर वाहन नियम, 2003 के नियम 67 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इस पहल से माल के परिवहन को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है, जिससे असम में ई-कॉमर्स क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ये निर्णय कर्मचारी कल्याण और आर्थिक विकास के प्रति असम सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, तथा शासन के प्रति संतुलित और प्रगतिशील दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं।

ड्रैगन ने फिर से ...

निर्माण में तेजी लाने के लिए 1 बिलियन डॉलर खर्च करने की योजना बना रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के बयान पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। भारत का कहना है कि उसका सुदूरवर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न अंग है, लेकिन चीन का कहना है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और उसने वहां भारतीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है। पिछले सप्ताह भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कजाकिस्तान में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की, जहां दोनों ने अपनी सीमा पर मुद्दों को हल करने के प्रयासों को तेज करने पर सहमति व्यक्त की।

एचआईवी से छात्रों की...

से 47 की मृत्यु हो गई। यह रिपोर्ट है भ्रामक है क्योंकि कुल आंकड़े अप्रैल 2007 से मई 2024 तक संचयी हैं। कृपया इसे त्रिपुरा सरकार के आधिकारिक स्पष्टीकरण के रूप में नोट करें। यह स्पष्टीकरण त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (टीएसएसीएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि त्रिपुरा में एचआईवी से कम से कम सैंतालीस छात्रों की मौत हो गई है और 828 एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने महीने की शुरुआत में कहा था कि हमने अब तक 828 छात्रों को पंजीकृत किया है जो एचआईवी पॉजिटिव हैं। उनमें से 572 छात्र अभी भी जीवित हैं और खतरनाक संक्रमण के कारण हमने 47 लोगों को खो दिया है। इस महीने की शुरुआत में कई छात्र देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च अध्ययन के लिए त्रिपुरा से बाहर चले गए हैं। राज्य सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े अप्रैल 2007 से 17 वर्षों के मामलों के संचयी आंकड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा सरकार राज्य में एचआईवी/एड्स के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। यह हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ हालिया मीडिया रिपोर्टों के कारण संक्रमित छात्रों और मौतों की संख्या पर संदेह पैदा हो गया है। संबंधित विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि त्रिपुरा में कुल 828 छात्र एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं और 17 वर्षों की अवधि (अप्रैल, 2007 से मई, 2024 तक) में 47 की जान चली गई है। सभी प्रभावित छात्रों को एनएसीओ दिशानिर्देशों के अनुसार मुफ्त एंटी-रेट्रोवायरल उपचार (एआरटी) प्राप्त हुआ है या मिल रहा है। हालांकि, टीएसएसीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी भट्टाचार्य ने एचआईवी मामलों में वृद्धि के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बढ़ती समस्या को जिम्मेदार ठहराया है, विशेष रूप से संपन्न परिवारों के छात्रों और सरकारी कर्मचारियों के बीच। अक्सर, जब तक इन परिवारों को पता चलता है कि उनके बच्चे नशे की लत के शिकार हो गए हैं, तब तक दुर्भाग्यवश हस्तक्षेप के लिए बहुत देर हो चुकी होती है।

उपचुनाव : प. बंगाल में ...

से 20 अकेले राणाघाट-दक्षिण से हैं। हालांकि, उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज और कोलकाता के मानिकतला के शेष दो निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया कमोबेश शांतिपूर्ण रही। पहले चार घंटों में इन चार विधानसभा क्षेत्रों में औसत मतदान प्रतिशत 23.45 रहा, जिसमें रायगंज में सबसे अधिक 25.98, रानाघाट-दक्षिण में 23.32, बागदा में 22.63 और मानिकतला में सबसे कम 21.89 रहा। बागदा में भाजपा उम्मीदवार बिनय कुमार विश्वास को निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और वापस जाओ के नारे लगाने लगे। विश्वास ने मीडियाकर्मियों से कहा कि बूथ-जाम की शिकायतें मिलने के बाद मैं इस बूथ पर गया था। वहां पहुंचने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे आक्रामक तरीके से घेर लिया और यह स्पष्ट था कि वहां क्या चल रहा था। मैंने पूरे घटनाक्रम के बारे में निर्वाचन अधिकारियों को सूचित कर दिया है। बागदा में फिर से विवाद तब भड़क गया जब तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर को एक एसयूवी में घूमते हुए देखा गया, जिस पर वाहन के विंडशील्ड पर *भारत सरकार* का स्टिकर चिपका हुआ था। उनके साथ उनकी मां और तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य ममता बाला ठाकुर भी थीं। हालांकि, जब भाजपा ने इस मामले में सीईओ कार्यालय का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, तो स्टिकर पर सफेद कागज चिपकाकर उसे ढक दिया गया। इस बीच, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राणाघाट-दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के पूर्णनगर में गोलीबारी की शिकायतों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नादिया की जिला पुलिस ने मामले की एसडीपीओ स्तर की जांच शुरू कर दी है।

पीएम मोदी और ...

ऑस्ट्रिया की यह ऐतिहासिक यात्रा 4 दशकों के बाद हो रही है। इस दौरान दोनों नेताओं ने साझा पत्रकारवार्ता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रिफॉर्म पर सहमत हैं ताकि उन्हें समकालीन और प्रभावी बनाया जा सके। दोनों देश आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं और इस बात पर सहमत हैं कि इसे किसी भी रूप में स्वीकार्य और न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने विश्व में चल रहे विवादों जैसे यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विस्तार से बात की। वे पहले भी कह चुके हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है। साथ ही इस दौरान जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा हुई। जलवायु विषय में भारत आस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए टकराव और जैव-ईंधन गठबंधन जैसी पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। सहमति के बिन्दुओं पर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। साथ ही संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही। ऐसे में निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रिया के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि वे नए आर्थिक सहयोग तलाशें। आज उनके देश के भारत के साथ पहले से बेहतर आर्थिक और व्यापारिक संबंध हैं। जो आपसी विश्वास और भरोसे को दर्शाते हैं। वर्तमान में दोनों देशों का व्यापार 2.7 अरब यूरो है। 150 से अधिक ऑस्ट्रियाई व्यवसाय भारत में काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह संख्या बढ़ेगी। ऑस्ट्रिया में भारतीय निवेश भी होगा।

सामूहिक शक्ति से बनाएंगे ...

कि हम सबका सपना देश का विकास कर देश को विश्व गुरु बनाने के साथ सुखी, समृद्ध और आतंक व भय से मुक्त भारत बनाना है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों को याद करते हुए भारत की सांस्कृतिक समानता को रेखांकित करते हुए कहा कि यही भावना हमें आने वाले समय में महान देश बनने में सहायक होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि केवल विकास और संपत्ति जरूरी नहीं है। जरूरत है अपनी संस्कृति और मानवता के विकास को समझने की। उल्लेखनीय है कि भारत विकास परिषद की स्थापना सन् 1963 में भारतीय समाज का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से हुई। भारत विकास परिषद समाज के प्रबुद्ध, संपन्न एवं प्रभावी व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय, अराजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नि:स्वार्थ संगठन है, जो अपने सदस्यों के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग, असमर्थ एवं अशिक्षित वर्ग के प्रति सेवा कर नवीन पीढ़ी में देशभक्ति के संस्कारों, नि:स्वार्थ सेवा को सुसंस्कारित करता है जो राष्ट्र के निर्माण के महान कार्य में निरंतर सक्रिय है। वर्तमान में देश के सभी प्रदेशों में 1,600 से अधिक शाखाएं एवं 84,000 से अधिक सदस्य परिवार परिषद के माध्यम से राष्ट्र सेवा में संलग्न है। भारत विकास परिषद के संस्थापक (स्व.) डा सूरज प्रकाश जी के जन्मदिवस (27 जून) से स्थापना दिवस (10 जुलाई) के मध्य आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत देशभर में परिषद की विभिन्न शाखाओं में सेवा, संपर्क और संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें मुख्यत: ब्लड डोनेशन कैंप, सिलाई मशीन वितरण, दिव्यांग सहायता शिविर, एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त अभियान, जरूरतमंद छात्रों को सहयोग (किताबें यूनिफार्म, छात्रवृति इत्यादि), पर्यावरण से सम्बंधित जल संरक्षण, जैविक खाद, प्रदूषण मुक्त जगरूकता अभियान एवं पौधरोपण अभियान रहा। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन ने सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए बताया कि किस तरह भारत विकास परिषद भारत के नवनिर्माण में जुटा है। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कार्यक्रम के संयोजक कर्नल सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में दिल्ली एवं आस पास से लगभग 1000 से ज्यादा प्रबुद्ध उद्योगपति एवं व्यवसायी, समाजसेवी, विश्वविद्यालयों से शिक्षक, डॉक्टर्स, अधिवक्ता सम्मिलित हुए।

जम्मू-कश्मीर से अवैध ...

विवरण इकट्ठा करने और नियमित आधार पर एक अद्यतन डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने का काम सौंपा गया है। एक आदेश में सरकार के प्रमुख सचिव, गृह विभाग, चंद्राकर भारती ने कहा कि 2011 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। पैनल की अध्यक्षता गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव करेंगे। पैनल के अन्य सदस्यों में पंजाब के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ), जम्मू और श्रीनगर मुख्यालय के आपराधिक जांच विभाग (विशेष शाखा), और सभी जिला एसएसपी और एसपी (विदेशी पंजीकरण), राज्य समन्वयक, एनआईसी के साथ शामिल हैं। आदेश के अनुसार, समिति को एक मासिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इसे हर महीने की पांचवीं तारीख तक केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को सौंपना होगा। इसके अतिरिक्त, गृह विभाग ने पैनल को केंद्र शासित प्रदेश में ट्रेसिंग और निर्वासन प्रयासों के समन्वय और निगरानी करने का निर्देश दिया है। पैनल संबंधित हितधारकों के लिए इन मामलों की स्थिति की निगरानी और अद्यतन करने के साथ-साथ विभिन्न अदालतों में चल रहे मामलों पर किसी भी जानकारी का प्रसार करने के लिए जिम्मेदार होगा।

अमेरिका ने भी माना...

युद्ध के बीच पहली बार प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंचे थे। मॉस्को में गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने साफ तौर पर रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे जा रहे लोगों, खासकर बच्चों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने दो टूक में कहा कि वर्तमान समय युद्ध का नहीं है। इस युद्ध में अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है। पीएम मोदी की रूस यात्रा पर अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका का मानना है कि रूस और भारत के अच्छे संबंध की वजह से इस युद्ध पर लगाम लगाया जा सकता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे से जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक रणनीतिक भागीदार हैं। दोनों देशों के बीच हर मुद्दों पर स्पष्ट बातचीत होती है। यूक्रेन की बात आती है तो भारत सहित सभी देश स्थायी शांति हासिल करने के प्रयासों का समर्थन करते हैं। कैरिन जीन-पियरे ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि भारत के पास ये क्षमता है कि वो रूस से बातचीत कर युद्ध को रुकवा सकता है। हालांकि, युद्ध को रोकने का आखिरी राष्ट्रपति पुतिन का है। राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध शुरू किया, और वह युद्ध समाप्त कर सकते हैं।

रूसी सेना में कार्यरत ...

कहा कि रूसी पक्ष ने सभी भारतीय नागरिकों को रूसी सेना से जल्द सेवामुक्त करने का वादा किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने उन भारतीय नागरिकों को शीघ्र सेवामुक्त करने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया, जिन्हें गुमराह करके रूसी सेना में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और रूसी पक्ष ने सभी भारतीय नागरिकों को जल्द सेवामुक्त करने का वादा किया। क्वात्रा ने कहा कि दोनों पक्ष इस विषय पर काम करेंगे कि भारतीयों को कितनी तेजी से स्वदेश वापस लाया जा सके। एक प्रश्न के उत्तर में क्वात्रा ने कहा कि भारत का अनुमान है कि रूसी सेना में कार्यरत उसके नागरिकों की संख्या लगभग 35 से 50 के बीच होगी, जिनमें से 10 को पहले ही वापस लाया जा चुका है।

दिल्ली में कंपनियों ...

को मिलने वाले बिलों में टैरिफ में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक यह वृद्धि दो बीएसईएस कंपनियों - बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। हालांकि राहत की बात है कि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने अपनी दरों में कोई वृद्धि नहीं की है। वहीं बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने कीमतों में बढ़ोतरी की है। बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) के अंतर्गत आने वाले इलाकों में टैरिफ में 6.15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसमें पूर्वी और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्से शामिल हैं। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) ने 8.75 फीसदी की बढ़ोतरी लागू की है। इससे दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली के निवासियों पर असर पड़ेगा। बिजली दरों में यह बढ़ोतरी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट (पीपीएसी) के तहत की गई है। यह समायोजन बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदते समय होने वाली लागत को कवर करने के लिए किया जाता है। बढ़ी हुई लागत को फिर उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिलों के माध्यम से दिया जाता है। मई से जुलाई 2024 तक दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों के लिए कुल बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) अलग-अलग होगी। एनडीएमसी का कुल पीपीएसी सबसे अधिक 38.75 फीसदी है, उसके बाद टीपीडीडीएल का 37.88 फीसदी, बीवाईपीएल का 37.75 फीसदी और बीआरपीएल का 35.83 फीसदी है। इसमें पिछले बकाये पर मौजूदा पीपीएसी और अतिरिक्त वर्तमान पीपीएसी शामिल है, जिसमें एनडीएमसी और टीपीडीडीएल प्रत्येक अपनी मौजूदा दरों में 8.75 फीसदी, बीवाईपीएल 6.15 फीसदी और बीआरपीएल 8.75 फीसदी जोड़ रहे हैं। टैरिफ में यह वृद्धि 1 मई से शुरू होकर तीन महीने के लिए प्रभावी रहेगी। इस अवधि के बाद, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) स्थिति की समीक्षा करेगा और बिजली कंपनियों की याचिकाओं के आधार पर आगे के आदेश जारी करेगा। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब बिजली के बिल में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के लिए यह वृद्धि एक बोझ की तरह है, खासकर गर्मियों के महीनों के दौरान जब एयर कंडीशनिंग और कूलिंग उपकरणों के उपयोग के कारण बिजली की खपत आम तौर पर अधिक होती है। गौरतलब है कि दिल्ली के अन्य इलाकों में बिजली पहुंचाने वाली कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने अपनी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इन इलाकों के ग्राहकों को फिलहाल बिजली बिल में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। बीआरपीएल और बीवाईपीएल द्वारा हाल ही में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के कारण दिल्ली में बिजली आपूर्ति की मांग में वृद्धि के बीच कई निवासियों को अधिक बिल का भुगतान करना पड़ा है। हालांकि यह वृद्धि फिलहाल तीन महीने के लिए निर्धारित की गई है, लेकिन डीईआरसी द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले निर्णय शहर में बिजली की लागत पर दीर्घकालिक प्रभाव को निर्धारित करेंगे।

एपीसीसी की अनुशासन समिति की पहली बैठक आयोजित

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की अनुशासन कार्रवाई समिति की पहली बैठक बुधवार को गुवाहाटी के राजीव भवन में एपीसीसी अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा की पहल और उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में नवगठित अनुशासन कार्रवाई समिति के अध्यक्ष नृपेन ठाकुरिया, सह-अध्यक्ष बबीता शर्मा और सदस्य-सचिव एडवोकेट शिराजुल हुसैन सैकिया ने भाग लिया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों से संबद्ध शिकायतों के संबंध में सभी पार्टी सदस्यों को एक आधिकारिक नोटिस दिया गया है। वर्तमान में, असम पीसीसी को 6 जिलों से 35 शिकायतें मिली हैं। शिकायतों पर गौर करने के बाद समिति के सदस्य संबंधित जिलों का दौरा करेंगे और एपीसीसी अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा और एआईसीसी महासचिव (असम प्रभारी) जितेंद्र सिंह को मामलों की हकीकत से अवगत कराएंगे। समिति द्वारा विचार-विमर्श के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

एसएसबी ने किया आपदा प्रबंधन पर विशेष शिविर का आयोजन

गुवाहाटी (हिंस)। आरआरटी एसएचक्यू एसएसबी रंगिया ने डीआईजी राजीव राणा के मार्गदर्शन और निर्देशों के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई पुठिमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सहयोग से नब्यज्योति क्लब, पलारा (कामरूप) में *युवाओं के लिए स्वस्थ समाज* विषय के तहत आपदा न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति पर विशेष शिविर का आयोजन किया। आरआरटी एसएचक्यू रंगिया के प्रभारी अधिकारी ने प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा से संबंधित आपदा और पीड़ितों के बचाव कार्यों और सुरक्षा सावधानियों के साधनों पर पावरपॉइंट प्रस्तुतियों के साथ प्रतिभागियों को अवगत कराया। एएसआई (जीडी) बीएस देवरी, हेड कांस्टेबल धनेंद्र साहू और आरआरटी एसएचक्यू रंगिया की टीम ने डूबने से बचाव, तात्कालिक तरीकों और अन्य उपकरणों के उपयोग, बचाव और राहत कार्य पर व्यावहारिक प्रदर्शनों के साथ कक्षाएं लीं। एनएसएस के विद्यार्थियों और सभी प्रतिभागियों को उपकरणों और गैजेट्स, बचाव रणनीति, व्यावहारिक प्रदर्शन के तरीके, प्राथमिक चिकित्सा, एमएफआर, सीपीआर, अग्निशमन आदि से परिचित कराया गया। शिविर में सेवानिवृत्त प्राचार्य गणेश चंद्र शर्मा, प्राचार्य, शिक्षक, छात्र (एनएसएस सदस्य) और इलाके के आम लोगों ने भाग लिया। आपदा प्रबंधन के अलावा अधिकारी ने प्रतिभागियों से जागरूकता फैलाकर समाज में आत्महत्या की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार नागरिक के रूप में सकारात्मक भूमिका निभाने का अनुरोध किया। छात्रों ने अपना उत्साह व्यक्त किया।

इब्राहिम अली की हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल बरामद

गुवाहाटी (हिंस)। भवानीपुर के धुमारकुर में युवा व्यवसायी इब्राहिम अली को उसके आवास पर गोली मारने के सनसनीखेज मामले में बजाली पुलिस ने एक पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने धुमारकुर के पास बजाली में तालतल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जमीन में गाड़कर रखा गया था। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई की रात को इब्राहिम अली की हत्या हुई थी। इसके मुख्य मास्टरमाइंड मनोहर अली के कुबूलनामे के आधार पर पुलिस ने पिस्तौल बरामद करने में कामयाबी हासिल की। मनोहर अली ने इब्राहिम अली की हत्या की थी। उसे पिस्तौल की गोलियों से छलनी कर दिया था। फिलहाल मुख्य आरोपी मनोहर अली के साथ चार अन्य आरोपी दस दिन की पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस सभी हत्यारों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने 2 जुलाई को भवानीपुर के राजाखाट से कुल पांच लोगों को और 3 जुलाई को गुवाहाटी के एक लॉज से चार लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, आप नेता होंगे कांग्रेस में शामिल, आप ने किया खारिज

गुवाहाटी। आज असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेता और कार्यकर्ता और कार्यकारी सदस्य कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वे हैं बिमल हजारिका, नीलकांत मिसिंग, कार्तिक शैकिया, अजीत मुरा, सुखराम भक्त, विजय मुरा, मैना सिंह सूबेदार, उमेश चंद्र सूबेदार, जीत तेरान, मानव इंति, जॉनसन कोंवर, मोजम्मिल अली और सोहेबुल हुसैन। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों में असम अनुसूचित जाति विकास निगम के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र नाथ दास भी हैं. उन्होंने कहा कि हम देश और राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा रखने वाले हर सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का आग्रह करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं देशभक्तों के लिए हमेशा खुली हैं। असम सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक ने एक अधिसूचना जारी की है कि भारत में कहीं से भी लोग स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (पीआरसी) के बिना असम के शिक्षा विभाग में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उस नोटिस को हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने अमान्य घोषित कर दिया था। यदि मुख्यमंत्री का बयान सच है, तो उच्च शिक्षा निदेशक को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने चुनौती दी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी (आप) इस समय असम में संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया में है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही राज्य समितियों, जिला समितियों और पार्टी के अन्य सहयोगी संगठनों की सभी समितियों को भंग कर दिया है। इसके कई कारण हैं आपको कांग्रेस पार्टी में क्यों नहीं शामिल होना चाहिए। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आपको कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की खबरों का कोई आधार नहीं है अन्य पार्टियां ऐसे समय में जब कोई समितियां नहीं हैं, पार्टी के उत्तर पूर्व पर्यवेक्षक राजेश शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी के वफादार नेता और कार्यकर्ता पार्टी संगठन की नींव को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य में जल्द ही नई समितियां बनाई जाएंगी। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आप में कोई गिरावट नहीं है। पार्टी के उत्तर पूर्व पर्यवेक्षक राजेश शर्मा ने आप मीडिया समन्वयक अब्दुल अलीम द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

मुख्यमंत्री संग्रहालय की स्थापना को लेकर डॉ. शर्मा ने की बैठक

गुवाहाटी (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने शिक्षा मंत्री डॉ. रोनोज पेगू की उपस्थिति में आज जनता भवन में मुख्यमंत्री संग्रहालय की स्थापना पर चर्चा करने के लिए खिलंजिया जनजातीय विश्वास और सांस्कृतिक विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री संग्रहालय की तर्ज पर असम में मुख्यमंत्री संग्रहालय की स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने पहले संग्रहालय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, इतिहासकारों, वास्तुकारों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का परामर्श दिया। उक्त समिति प्रधानमंत्री संग्रहालय का निरीक्षण करके इसके निर्माण से संबद्ध लोगों से मुलाकात करके योजना तैयार करने का परामर्श दिया। समाप्त

असम-मेघालय सीमा पर अवैध लकड़ी जब्त

ग्वालपाड़ा (हिंस)। ग्वालपारा जिले में लकड़ी की तस्करी का कारोबार जारी है। वन विभाग ने एक सूचना के बाद दुधनोई के असम-मेघालय सीमावर्ती क्षेत्र में छापा मारा कर कीमती लकड़ी बरामद की। वन विभाग के सूत्रों ने बुधावार को बताया है कि इस अभियान में वन विभाग असम-मेघालय सीमा पर चिलुक बाखारापारा में बड़ी मात्रा में साल के पेड़ की कुंदों (52 कुंदों) को जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। जब्त किए गए साल के पेड़ के तने चिलूक बाखारापारा में रखे गए थे। वन विभाग के अधिकारी अवैध रूप से रखे साल के पेड़ के कुंदों को जब्त कर दुधनई प्रखंड वन अधिकारी के कार्यालय ले आए। दुधनोई प्रखंड वन अधिकारी ने बताया कि जब्त साल की लकड़ी का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपये होगा। हालांकि, इस संबंध में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

सिपाझार राजस्व सर्किल के आठ गांव बाढ़ की चपेट में

दरंग (हिंस)। असम के 30 से अधिक जिले राज्य में आई दूसरी बार की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस कड़ी में पिछले दो सप्ताह से दरंग जिलांतर्गत सिपाझार राजस्व सर्किल के आठ गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र नद के बाढ़ के पानी से अभी भी सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। बाढ़ पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उनके पास अभी तक कोई सरकारी राशन की व्यवस्था नहीं पहुंची है। हालांकि, राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी आवश्यक व्यवस्था करने में जुटी हुई है। स्वयं मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा प्रतिदिन बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन ने पशुओं के लिए भी कोई आवश्यक चारे की व्यवस्था नहीं है। जिसके चलते बाढ़ प्रभावित बेहद परेशानी में दिन काटने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन अंदरुनी इलाकों में अभी भी सरकारी मदद के नहीं पहुंचने का आरोप लगाया जा रहा है।

जाने माने अर्थशास्त्री, निबंधकार डॉ. अनिल कुमार सैकिया का निधन

जोरहाट (हिंस)। राज्य के जाने माने अर्थशास्त्री, निबंधकार डॉ. अनिल कुमार सैकिया का निधन हो गया, जिसके चलते शोक की लहर दौड़ गई है। सैकिया का बीती देर रात को जोरहाट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल (जेएमसीएच) में निधन हो गया। घर पर अचानक बीमार पड़ने के बाद सैकिया को पहले एफआरयू और फिर बेहतर इलाज के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल में उनका निधन हो गया। वह कई समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के साथ एक नियमित स्तंभकार के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। सैकिया ककजान कॉलेज के रिटायर्ड एकेडमिक वाइस प्रिंसिपल थे। डॉ. सैकिया ने अर्थशास्त्र पर कई किताबें लिखी हैं और असमिया साहित्यिक भंडार को श्रमृद्ध किया है। सैकिया असमिया कविता पत्रिका काव्यश्री के प्रकाशक थे। उनके निधन पर साहित्य जगत के साथ ही उनके शुभचिंतकों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।

शिवसागर में बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों से बचाव में जुटा प्रशासन

शिवसागर (हिंस)। राज्य में बाढ़ के चलते स्थिति बद से बदतर हो गई है। शिवसागर जिले के विभिन्न हिस्से अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के पानी के बाद विभिन्न बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए शिवसागर स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार की तैयारियां की हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में कुछ जानकारी सार्वजनिक की गई है। शिवसागर जिले में दिमागी बुखार जैसे मामलों के रोगियों की संख्या 25 पहुंच गई है, जिनमें से 12 की पहचान जापानी इंसेफेलाइटिस के रूप में की गई है। जापानी इंसेफेलाइटिस से मरने वालों की संख्या जिले में तीन हो गई है। शिवसागर स्वास्थ्य विभाग ने इंसेफेलाइटिस बीमारी से पीड़ित मरीजों के आवास के आसपास कीटनाशकों के छिड़काव की व्यवस्था की है। मच्छरों की वृद्धि को कम करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के बीच ओआरएस पैकेट वितरित करने के लिए विशेष उपाय किए हैं ताकि लोग दस्त जैसी बीमारियों से प्रभावित न हों। विभिन्न स्थानों पर औषधीय उपचार द्वारा जापानी एन्सेफलाइटिस जैसी बीमारियों से बचाव के प्रयास जारी हैं। स्वास्थ्य शिक्षकों को उन तरीकों से अवगत कराने के लिए भी उपाय किए गए हैं, जिनसे वे विभिन्न बीमारियों से स्वयं को बचा सकते हैं।

स्वागत अस्पताल ने जटिल हर्निया उपचार के लिए प्रस्तुत की नई तकनीक

गुवाहाटी (हिंस)। राजधानी गुवाहाटी के स्वागत अस्पताल ने जर्मन चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. गेरियन हिल द्वारा शुरू की गई एक नई अभिनव हर्निया तकनीक फेसियोटेंस की शुरुआत की घोषणा की। इस तकनीक से जटिल हर्निया का इलाज जाएगा, जिनका इलाज अक्सर पारंपरिक तरीकों से नहीं किया जा सकता है। जटिल हर्निया सर्जनों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करती रहती है। पिछले दो दशकों में चिकित्सा क्षेत्र में न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिसमंन अधिकांश हर्निया उपचारों के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। फासिओटेंस हर्निया के उपचार में एक प्रमुख प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में, गंभीर रूप से विकृत पेट और 21 सेमी से अधिक के हर्निया गैप वाले एक मरीज का स्वागत अस्पताल में सफल ऑपरेशन किया गया है। बड़ी संतुष्टि के साथ उसे घर जाने के लिए छुट्टी दे दी गई। फासिओटेंस तकनीक की शुरुआत हर्निया के उपचार में एक मील का पत्थर है, जो जटिल पेट की दीवार दोष वाले रोगियों के लिए नई आशा प्रदान करती है। वर्तमान उपचार बहुत महंगे हैं क्योंकि, डिस्पोजेबल उपकरणों की लागत बहुत अधिक है लेकिन उम्मीद है कि समय के साथ लागत कम हो जाएगी। जल्द ही इस तकनीक को रोबोटिक सर्जरी के साथ जोड़ दिया जाएगा। प्रोफेसर सुभाष खन्ना के नेतृत्व में डॉ. सुप्रिया चौधरी, डॉ. अरिंदम बरुवा, डॉ. विश्वज्योति राभा और डॉ. कनिनिका दास और स्क्रब नर्स विद्यारानी देवी, लिपिका सैकिया और अलवनिशा दखार की सहायता से सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई।

मानसून के दौरान बार-बार आने वाली बाढ़ के खिलाफ महानगर के 300 निवासियों ने किया विरोध-प्रदर्शन

गुवाहाटी। रुक्मिणीगांव के कम से कम 300 निवासी बुधवार (10 जुलाई) को अपने इलाके में लगातार हो रही बाढ़ की समस्या के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर एकत्र हुए। इस प्रदर्शन में बार-बार होने वाली जलभराव की समस्या से उनकी हताशा को उजागर किया गया, जिसने उनके दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सुबह करीब 9 बजे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें निवासियों ने प्रभावी जल निकासी व्यवस्था की कमी और स्थानीय अधिकारियों की अपर्याप्त प्रतिक्रिया के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने तख्तियां ले रखी थीं और नारे लगाए, जिसमें सरकार से उनकी दुर्दशा को प्राथमिकता देने और त्वरित कदम उठाने का आग्रह किया गया। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि हम वर्षों से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा है। हर मानसून में हमारे घर और सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जिससे सामान्य जीवन जीना असंभव हो जाता है। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम अधिकारियों से बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक समाधान लागू करने की मांग की। इससे पहले 5 जुलाई को गुवाहाटी के एक निवासी ने अपने घर में आई भीषण बाढ़ की तस्वीरें साझा की थीं। अमरज्योति बोरा, जिनका घर रुक्मिणीगांव में है, ने 4 जुलाई की रात शहर में भारी बारिश के बाद अपने कार पार्किंग क्षेत्र को पानी में डूबा हुआ और पानी उनके घर में घुसता हुआ दिखाते हुए तस्वीरें पोस्ट की थीं। असम के गुवाहाटी में 4 जुलाई को नाले में गिरे 8 वर्षीय बच्चे का शव 7 जुलाई की सुबह बरामद हुआ, जिसके बाद तलाशी अभियान का दुखद अंत हुआ। माता-पिता हीरालाल और उनकी पत्नी ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में शव की पहचान की। 17 जून की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारी बारिश के कारण अनिल नगर और चांदमारी क्षेत्रों सहित गुवाहाटी के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव हो गया, जिससे सामान्य जनजीवन काफी बाधित हुआ। सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे शहर भर में निवासियों और यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

संगीत की विशेष कलाकारी कार्यशाला 21 से

अभिनेता पंकज पल्लव शर्मा की नई फिल्म का काम प्रारंभ

रंगिया (विभास)। रंगिया में स्थापित सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, संगीत ग्रुप ऑफ क्रिएशन, पिछले कई वर्षों से अभिनय के शौकीनों को अभिनय प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। वहीं नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा, हर साल गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक विशेष अभिनय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस वर्ष की विशेष कार्यशाला 21 जुलाई से रंगिया के आईटीआई में शुरू होगी। इस कार्यशाला में नवंबर से शूट होने वाली पंकज पल्लव शर्मा की नई फिल्म के लिए कलाकारों का चयन और प्रशिक्षण भी शामिल होगा। उल्लेखनीय है कि बर्ष 2021मे अभिनेता पंकज पल्लव शर्मा के निर्देशन में पहली असमिया फिल्म *दिठोकोट हेराल सापोन* सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को कई पुरस्कार भी मिले है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिनेता पंकज पल्लव शर्मा की दूसरी फिल्म का प्रारंभिक काम पूरा हो गया है। निर्देशक शर्मा ने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग नवंबर से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि संगीत का काम भी शुरू हो गया है। पंकज पल्लव शर्मा ने बताया है कि वे नई फिल्म में भी नए प्रतिभाशाली कलाकारों को मौका देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी 21जुलाई से शुरू होने वाली सात दिवसीय कार्यशाला नई फिल्म के लिए अधिक गुरूत्वपूर्ण होगी। वहीं बताया गया है कि इच्छुक लोग 8876348062, 9954628228, 7896796668 एवं 8011479083 मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं।

संपादकीय

ईरान के सुधारवादी राष्ट्रपति

उदारवादी सुधारवादी मसूद पेजेशकियान का ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए जीतना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ईरान में दोबारा चुनाव कराना पड़ा, क्योंकि प्रथम चरण में किसी भी प्रत्याशी को 50 फीसदी वोट नहीं मिले थे। दूसरे चरण में मसूद ईरान का नया और नरम चेहरा थे, जो समग्र तौर पर सुधारों के पक्षधर थे। उनके प्रतिपक्ष में ईरान का कट्टरवाद था। अब मसूद की जीत हुई है, तो माना जा रहा है कि अभी तक बंद, कट्टरपंथी और रूढ़िवादी ईरान के नए आयाम खुलेंगे। ईरान सांस्कृतिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और टकरावों से घिरा देश रहा है। अधिकतर पड़ोसी अरब देशों और पश्चिम से ईरान के टकरावपूर्ण और लंबे तनाव के समीकरण आज भी हैं। ईरान की जनता ने उदारवादी, सुधारवादी, नरम राष्ट्रपति का चुनाव किया है। साफ मायने हैं कि ईरान अब शेष दुनिया के साथ अमन-चैन के रिश्ते चाहता है, इंटरनेट को स्वतंत्र और मुक्त करने का पक्षधर है और खासकर औरतों पर से सामाजिक पाबंदियों और बंदिशों को उठाना चाहता है। दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके चुनावी प्रतिद्वंद्वी सईद जलीली की ईरान के भीतर और विदेशों के संदर्भ में नीतियां 'कट्टरवादी' थीं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद के प्रतिपक्ष की सोच भी कट्टरपंथी थी। प्रतिपक्षी नेता जेल में भी रहे थे, लेकिन मसूद ने अपने प्रचार के लिए जो गीत रचा था, उसका सारांश यह था कि गलियों में नाचो, चुंबन लेते वक्त मत डरो और मेरी बहन, तुम्हारी बहन और हमारी बहन... ! उसके उलट प्रतिपक्षी ने ईरान की औसत औरत पर कड़े नियंत्रणों की पैरवी की, ताकि परिवार नामक संस्थान की पवित्रता बरकरार रह सके। राष्ट्रपति मसूद ने संकेत दिए हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में बदलावों के अध्याय जोड़े जाएंगे। उन्होंने लोगों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया और ईरान के लोगों की चिंताओं को ध्यान से सुनने का वायदा दोहराया। सामाजिक स्तर पर सुधार किए जाएंगे। ईरानी औरत की उम्मीदें जगी हैं, लेकिन ईरान का इजरायल-विरोध जारी रहेगा। ईरान गाजा पट्टी, लेबनान, यमन का साथ देता रहेगा। ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तनावपूर्ण सरहदों को नए आकार देने की भूमिका निभाते हुए काबुल और रावलपिंडी के बीच संतुलन स्थापित करना चाहता है। यह भूमिका ईरान का राष्ट्रीय सिद्धांत भी है। बहरहाल वहां की आर्थिक जरूरतों के मद्देनजर राष्ट्रपति मसूद चाहते हैं कि अमरीका अपनी पाबंदियां उठाए। उस संदर्भ में ईरान के रहस्यमयी 'परमाणु कार्यक्रम' का जो गतिरोध अमरीका के साथ रहा है, उसका समाधान शीघ्र ही निकालना होगा। ईरान की रूस और चीन के साथ जो सामरिक साझेदारी है, उस पर भी अमरीका को आश्वस्त करना होगा। अमरीका समेत पश्चिमी देशों के साथ ईरान के तनावपूर्ण संबंध राष्ट्रपति मसूद की सबसे गंभीर चुनौती है। जहां तक भारत-ईरान संबंधों का सवाल है, उसकी बुनियाद कच्चा तेल है। भारत के लिए ईरान कभी सबसे बड़ा तीसरा, तो कभी दूसरा देश रहा है, जो कच्चा तेल सप्लाई करता रहा है। बुनियादी तौर पर ईरान तेल के मामले में भारत का बहुत बड़ा स्रोत रहा है। चूंकि अमरीका ने ईरानी तेल के आयात पर पाबंदी चस्पा कर दी थी, लिहाजा उसके प्रभाव में भारत ने भी वित्त वर्ष 2019 में ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था। अब ईरान 90 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल चीन को भेज रहा है। भारत ने रूस से इतनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया है कि रूस की ढहती अर्थव्यवस्था फिर से खिलने लगी है। अमरीका और यूरोपीय देशों की आर्थिक पाबंदियों से रूस को भारत ने धराशायी नहीं होने दिया। ईरान के साथ भी भारत के पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ईरान और अमरीका के बीच अमन-चैन के संबंध बनते हैं, तो वे भारत के लिए बेहद सुखद साबित हो सकते हैं। यदि ट्रंप दोबारा अमरीका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो ईरान के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। बहरहाल भारत को मसूद-युग में नई संभावनाओं को लपकना चाहिए।

ईरान में दोबारा चुनाव कराना पड़ा, क्योंकि प्रथम चरण में किसी भी प्रत्याशी को 50 फीसदी वोट नहीं मिले थे। दूसरे चरण में मसूद ईरान का नया और नरम चेहरा थे, जो समग्र तौर पर सुधारों के पक्षधर थे। उनके प्रतिपक्ष में ईरान का कट्टरवाद था। अब मसूद की जीत हुई है, तो माना जा रहा है कि अभी तक बंद, कट्टरपंथी और रूढ़िवादी ईरान के नए आयाम खुलेंगे। ईरान सांस्कृतिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और टकरावों से घिरा देश रहा है। अधिकतर पड़ोसी अरब देशों और पश्चिम से ईरान के टकरावपूर्ण और लंबे तनाव के समीकरण आज भी हैं। ईरान की जनता ने उदारवादी, सुधारवादी, नरम राष्ट्र पति का चुनाव किया है। साफ मायने हैं कि ईरान अब शेष दुनिया के साथ अमन-चैन के रिश्ते चाहता है, इंटरनेट को स्वतंत्र और मुक्त करने का पक्षधर है और खासकर औरतों पर से सामाजिक पाबंदियों और बंदिशों को उठाना चाहता है। दिवंगत राष्ट्र पति इब्राहिम रईसी और उनके चुनावी प्रतिद्वंद्वी सईद जलीली की ईरान के भीतर और विदेशों के संदर्भ में नीतियां 'कट्टरवादी' थीं।

विकसित देशों में तो पति-पत्नि के बीच तलाक की दर 50 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है

भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुरूप हो इस वर्ष का बजट

प्रह्लाद सबनानी

आर्थिक क्षेत्र में बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यह देश इन समस्याओं का हल निकाल ही नहीं पा रहे हैं। नियंत्रण से बाहर होती मुद्रा स्फीति की दर, लगातार बढ़ता कर्ज का बोझ, प्रौढ़ नागरिकों की बढ़ती जनसंख्या के चलते सरकार के खजाने पर बढ़ता आर्थिक बोझ, बजट में वित्तीय घाटे की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आदि कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जिनका हल विकसित देश बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी नहीं निकाल पा रहे हैं एवं इन देशों का सामाजिक तानाबाना भी छिन्नभिन्न हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्णकालिक बजट माननीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारतीय संसद में 23 जुलाई 2024 को पेश किया जा रहा है। वर्तमान में भारत सहित विश्व के लगभग समस्त देशों में पूंजीवादी नीतियों का अनुसरण करते हुए अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। परंतु, हाल ही के वर्षों में पूंजीवादी नीतियों के अनुसरण के कारण, विशेष रूप से विकसित देशों को, आर्थिक क्षेत्र में बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यह देश इन समस्याओं का हल निकाल ही नहीं पा रहे हैं। नियंत्रण से बाहर होती मुद्रा स्फीति की दर, लगातार बढ़ता कर्ज का बोझ, प्रौढ़ नागरिकों की बढ़ती जनसंख्या के चलते सरकार के खजाने पर बढ़ता आर्थिक बोझ, बजट में वित्तीय घाटे की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आदि कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जिनका हल विकसित देश बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी नहीं निकाल पा रहे हैं एवं इन देशों का सामाजिक तानाबाना भी छिनभिन्न हो गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चूंकि व्यक्तिवाद हावी रहता है अतः स्थानीय समाज में विभिन्न परिवारों के बीच आपसी रिश्ते केवल आर्थिक कारणों के चलते ही टिक पाते हैं अन्यथा शायद विभिन्न परिवार एक दूसरे से रिश्तों को आगे बढ़ाने में विश्वास ही नहीं रखते हैं। कई विकसित देशों में तो पति-पत्नि के बीच तलाक की दर 50 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। अमेरिका में तो यहां तक कहा जाता है कि 60 प्रतिशत बच्चों को अपने पिता के बारे में जानकारी ही नहीं होती है एवं केवल माता को ही अपने बच्चे का लालन-पालन करना होता है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है एवं यह बच्चे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, समाज में हिंसा की दर बढ़ रही है तथा वहां की जेलों में कैदियों की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। इन देशों के नागरिक अब भारत की ओर आशाभारी नजरों से देख रहे हैं एवं उन्हें उम्मीद है कि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का हल भारतीय सनातन संस्कृति में से ही निकलेगा। अतः इन देशों के नागरिक अब भारतीय सनातन संस्कृति की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। भारत में वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ हद्द तक वामपंथी नीतियों का अनुसरण करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर ले जाने का प्रयास किया गया था। परंतु, वामपंथी विचारधारा पर आधारित आर्थिक

नीतियों ने बहुत फलदायी परिणाम नहीं दिए अतः बहुत लम्बे समय तक यह नीतियां आगे नहीं बढ़ सकीं। हालांकि बाद के खंडकाल में तो वैश्विक स्तर पर वामपंथी विचारधारा ही धराशायी हो गई एवं सोवियत रूस कई टुकड़ों में बंट गया। आज तो रूस एवं चीन सहित कई अन्य देश जो पूर्व में वामपंथी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों को अपना रहे थे, ने भी पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों को अपना लिया है। भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं पूरे विश्व के आर्थिक पटल पर भारत का डंका बजा करता था। एक ईसवी से लेकर 1750 ईसवी तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत के आसपास बनी रही है। उस समय पर भारतीय आर्थिक दर्शन पर आधारित आर्थिक नीतियों का अनुपालन किया जाता था। मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, ऋण का बोझ, वित्तीय घाटा, बुजुर्गों को समाज पर बोझ समझना, बच्चों का हिंसक होना, सामाजिक तानाबाना छिनभिन्न होना आदि प्रकार की समस्याएं नहीं पाई जाती थीं। समाज में समस्त नागरिक आपस में भाईचारे का निर्वहन करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते थे। प्राचीन काल में भारत के बाजारों में विभिन्न वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसके चलते मुद्रा स्फीति जैसी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में कई ग्रामों को मिलाकर हाट लगाए जाते थे जहां खाद्य सामग्री एवं अन्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता रहती थी, कभी किसी उत्पाद की कमी नहीं रहती थी जिससे वस्तुओं के दाम भी नहीं बढ़ते थे। बल्कि, कई बार तो वस्तुओं की बाजार कीमत कम होती दिखाई देती थी क्योंकि इन वस्तुओं की बाजार में आपूर्ति, मांग की तुलना में अधिक रहती थी। माननीय वित्तमंत्री महोदय को भी देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए बाजारों में उत्पादों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए न कि ब्याज दरों को बढ़ाकर बाजार में वस्तुओं की मांग को कम किए जाने का प्रयास किया जाए। विकसित देशों द्वारा अपनाई गई आधुनिक अर्थशास्त्र की यह नीति पूर्णत असफल होती दिखाई दे रही है और इतने लम्बे समय तक ब्याज दरों को ऊपरी स्तर पर रखने के बावजूद मुद्रा स्फीति की दर वांछनीय स्तर पर नहीं आ पा रही है। भारत को इस संदर्भ में पूरे विश्व को राह दिखानी चाहिए एवं आधुनिक अर्थशास्त्र के मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत को बाजार में वस्तुओं की मांग कम करने के स्थान पर वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए अर्थात आपूर्ति पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे मुद्रा स्फीति तो कम होगी ही परंतु साथ ही अर्थव्यवस्था में विकास की दर भी और तेज होगी क्योंकि वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ते रहने से विनिर्माण इकाईयों में गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। परंतु यदि वस्तुओं की मांग में कमी करते हुए मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास होंगे तो उत्पादों की मांग में कमी होने के चलते उत्पादों का निर्माण कम होने लगेगा, विनिर्माण इकाईयों में गतिविधियां कम होंगी एवं देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। मांग में कमी करने के प्रयास सम्बंधी सोच ही अमानवीय है। इसी प्रकार, प्राचीन भारत में ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र के साथ ही कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कई ग्रामों को मिलाकर हाट लगाए जाते थे, इन कृषि उत्पादों के साथ ही इन कुटीर एवं लघु उद्योगों में निर्मित उत्पाद भी बेचे जाते थे। अतः ग्रामीण इलाकों से शहरों की पलायन नहीं होता था तथा नागरिकों को रोजगार के अवसर ग्रामीण इलाकों में ही उपलब्ध हो जाते थे। आज की परिस्थितियों के बीच कृषि क्षेत्र तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों में ही रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित हो सकें। जनता पर करों के बोझ को कम करने के सम्बंध में भी विचार होना चाहिए। भारत के प्राचीन शास्त्रों में कर सम्बंधी नीति का वर्णन मिलता है जिसमें यह बताया गया है कि राज्य को जनता पर करों का बोझ उतना ही डालना चाहिए जितना एक मधुमक्खी फूल से शहद निकालती है। अर्थात, जनता को करों का बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाने बजट में भी आवश्यक वस्तुओं पर लागू करों की दरों को कम करने के प्रयास होने चाहिए।

दृष्टि कोण

खिलाडियों को प्रशिक्षण-संसाधनों की जरूरत

हमारा देश 'विचित्र किंतु सत्य' की पराकाष्ठा पर सदैव खरा उतरता आया है। क्षेत्र चाहे कोई भी क्यों न हो, इसे देवभूमि का प्रताप समझें या देश की माटी का हुनर, भाव चाहे कोई कुछ भी समझे, मगर असीमित संसाधनों व प्रतिभाओं से परिपूर्ण इस देश को पूरा विश्व समुदाय संज्ञान में लेने लगा है। लेकिन विडंबना यह है कि सब कुछ हो जाने के बाद उन प्रतिभाओं को पूछा जाता है कि तुम्हें सुविधाओं का अभाव तो नहीं है। फिर उन्हें शाबाशी दी जाती है, पीठ थपथपाई जाती है और पुरस्कारों की वर्षा की जाती है। देश-दुनिया में प्रशंसा का एक दौर चल पड़ता है। इन सबके पीछे वो खिलाड़ी व उनके प्रशिक्षक होते हैं, जिन्हें शुरुआती दौर में कोई नहीं पूछता। अगर पूछता है तो देश-प्रदेश के लिए मेडल लाने के बाद, मगर तब तक हजारों खेल प्रतिभाएं दम तोड़ चुकी होती हैं। आखिर कब तक यह विडंबना खिलाडियों का पीछा करती रहेगी? कुछ एक समर्थवान खेल संघों को छोडक़र बाकी सब खेलों में खिलाड़ी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बावजूद जी-जान लगाकर कभी सफल तो कभी असफल भी रहते हैं, मगर हिम्मत नहीं हारते। बल्कि स्वयं के विश्वास, हौसले व कुछ कर पाने की भावना के बूते अपने प्रयास जारी रखते हैं। सभी खेलों को बढ़ावा देने वाले व आवश्यक खेल संसाधनों की पूरे देश में कमी है। कोई भी इस ओर ध्यान देना क्यों आवश्यक नहीं समझता? क्योंकि सबको एक आदत सी हो गई है कि जब कोई खिलाड़ी या टीम प्रदेश या देश का नाम रोशन कर देगी तो खुशी के लम्हों में उनकी पीठ थपथपा देंगे, सभी खुश तो बात खत्म। मगर खेल प्रतिभाओं से परिपूर्ण इस देश में कब तक एक पारदर्शी खेल व संसाधनयुक्त नीति ग्रामीण स्तर तक पहुंच पाएगी? देश की खेल योजनाएं तो सभी जानते हैं, मगर हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई खेल योजना 'खेलेगा हिमाचल, बढ़ेगा हिमाचल' शुरू की है। अच्छी पहल है, स्वागत योग्य है, मगर उसमें अपनी क्षमता पर ओलंपिक से स्वर्ण जीतने पर 3 करोड़, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ व कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ की राशि विजेता खिलाड़ी को बतौर पुरस्कार प्रदान की जाएगी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 50 लाख, रजत पदक पर 30 लाख व कांस्य पदक जीतने पर 20 लाख की पुरस्कार राशि विजेता खिलाडियों को सरकार प्रदान करेगी। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों में भी एशियाई खेलों के बराबर पुरस्कार राशि विजेता खिलाडियों में वितरित की जाएगी। मगर ग्रामीण क्षेत्रों व बुनियादी स्तर पर खेल प्रतिभा को उभारने व प्रशिक्षित करने हेतु कब पूरे देश व हर राज्य स्तर पर पारदर्शी खेल नीति उतारने की पहल होगी? मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हर खेल क्षेत्र में प्रतिभा प्रभावित होती है। देश का नाम रोशन करने पर अनेकों प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराने आगे आ जाते हैं, मगर बुनियाद को मजबूत करने आज तक कोई भी आगे नहीं आया। ऐसा हमारे देश में क्यों होता है? हकीकत सभी जानते हैं, मगर समझना कोई नहीं चाहता। शायद समय आ गया है कि विभिन्न खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले सभी खेलों के खिलाडियों को भी देश की खेल व्यवस्था में सुधार करने व प्रोत्साहन देने हेतु आगे आना चाहिए। हर खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र या मनपसंद का एक खेल गोद लेकर, उसे प्रोत्साहित कर सकता है। जिस शुरुआती दौर से किस तरह खुद को निखार कर वे हीरे निकले हैं, अब उन हीरों को अपनी रौशनी से अन्य हीरों को तराशने में मदद करनी होगी। हर खेल को उसी खेल की मूल भावना से विकसित करना होगा। हर खेल के आवश्यक मूलभूत संसाधन व प्रशिक्षण चाहे जिला स्तर पर ही सही, मगर पूरे देश में खिलाडियों को उपलब्ध होने चाहिएं। तभी तो खेल प्रतिभाएं अपने प्रदेश व देश का नाम विश्व स्तर पर अंकित कर पाएंगी। परिवर्तन समय का नियम है। समय रहते देश-प्रदेश की खेल नीतियों में सार्थक परिवर्तन की बुनियादी स्तर के खिलाडियों को आवश्यकता है। हर खेल में निपुण प्रशिक्षकों को नियुक्त करने व आवश्यक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। नियमित प्रशिक्षण शिविर हर स्तर पर आयोजित करने होंगे व खेल प्रेमी शिक्षक-प्रशिक्षकों को विश्वास में लेकर ही बेहतर खेल परिणाम पाने की उम्मीद की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाली अपार खेल प्रतिभाओं तक सरकारों की बुनियादी सुविधाओं का न पहुंचना भी खिलाडियों को निरुत्साहित कर सकता है। 'खेलों से स्वास्थ्य', 'खेलो इंडिया, फिट इंडिया' जैसे अनेकों उपक्रम क्यों सीमित होकर रह जाते हैं? वक्त आ गया है कि बेहतर खेल परिणाम पाने की इच्छा में बेहतर खेल सुविधाएं सभी खेलों के खिलाडियों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला व खंड स्तर तक उपलब्ध करवाई जाएं। ग्रामीण ओलंपियाड जैसे कार्यक्रम, जो खिलाडियों को आगे बढने के लिए कारगर साबित हो सकते थे, फिलहाल दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। सफलता के बाद मात्र पीठ थपथपाने से खेल प्रतिभाएं शायद ही निखर पाएंगी।

कुछ अलग

संसद के सलीके

हमारी नई लोकसभा अभी बनी ही है, लेकिन चल नहीं पा रही। चल पाएगी, इसमें शक है। चलकर भी क्या कर पाएगी, कह नहीं सकते। कहावत बहुत पुरानी है जो हर अनुभव के साथ नई होती रहती है कि 'पूत के पांव पालने में ही दीख जाते हैं।' जो पांव दीख रहा है, वह शुभ नहीं है। यदि मैं भूलता नहीं हूं तो कवि विजयदेव नारायण साही ने इस कहावत में एक दूसरी मार्मिक पंक्ति जोड़ दी थी : 'पूत के पांव पालने में मत देखो, वह पिता के फटे जूते पहनने आया है।' इस लोकसभा के बारे में यही पंक्ति बार-बार मन में गूंज रही है। जिस पार्टी ने, जिन पार्टियों के साथ जोड़ बिठाकर सरकार बनाई है, उन सबको मालूम है कि यह वक्ती व्यवस्था है। कौन, पहले, किसे और कब लंगड़ी मारता है, इसी पर इस लोकसभा का भविष्य टिका है, और यह तो सारे संविधानतज्ञ जानते हैं कि लोकसभा के भविष्य पर ही सांसद नाम के निरीह प्राणियों का भविष्य टिका होता है। निरीह इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कम से कम 10 सालों से हमारे सांसदों का एक ही काम रहा है, जिसे वे बड़ी शिद्दत से निभाते हैं : सरकार की दी हुई मेज थपथपाना या भगवान की दी हुई हथेलियों से तालियां बजाना। विपक्ष भी ऐसा ही करता है। फर्क है तो बस इतना कि उसके पास कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। इस बार उसके पास एक 'छाया प्रधानमंत्री' जरूर है जिसकी छाया कब तक, कहां तक रहती है, देखना बाकी है। हम दुआ करते हैं कि अंग्रेजी के 'शैडो प्राइम मिनिस्टर' का मक्खीमार अनुवाद भले उसे 'छाया प्रधानमंत्री' कहे, नेता प्रतिपक्ष कभी इस प्रधानमंत्री की छाया न बनें। न उनकी छाया में रहें, न उनको छाया दें। ओम बिरला को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनाने के पीछे प्रधानमंत्री का एक ही मकसद था : विपक्ष को आखिरी हद तक अपमानित करना! बिरला कभी इस पद के योग्य नहीं थे, आज भी नहीं हैं। विद्वता, कार्यकुशलता, व्यवहार कुशलता, वाकपटुता तथा सदन में गरिमामय माहौल बनाए रखने जैसे किसी भी गुण से उनका नाता नहीं रहा है, यह हमने पिछले पांच सालों में देखा है। पता नहीं विपक्ष ने उनका इतना स्वागत व गुणगान क्यों किया! ओम बिरला ने पिछली संसद में जिस तरह विपक्ष को तिरस्कृत व अपमानित किया था, उसे ही दोहराने के लिए इस बार भी उन्हें ही प्रधानमंत्री ने आगे किया है, ताकि विपक्ष व देश समझे कि कहीं, कुछ भी बदला नहीं है। नई लोकसभा के पहले ही दिन वे अपने पुराने अवतार में दिखाई दिए। जिस असभ्यता से उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को अपमानित किया, शशि थरूर के 'जय संविधान' कहने से तिलमिलाए, विपक्ष के सांसदों को कब उठना-कब बैठना सिखाने की फब्ती कसी, वह सब यह समझने के लिए पर्याप्त है कि उन्हें क्या करने का निर्देश हुआ है। राहुल गांधी ने जब यह कहा कि उनका माइक बंद क्यों किया गया, तो अध्यक्ष का जवाब आया कि मैंने पहले भी यह व्यवस्था दी है कि मेरे पास माइक का कोई बटन नहीं है। क्या अध्यक्ष की जानकारी व अनुमति के बगैर ही कोई, कहीं से बैठकर लोकसभा की कार्रवाई में दखल दे रहा है? अगर ऐसा है तो अध्यक्ष चाहिए ही क्यों? जो अनदेखा-अनजाना आदमी बटन बंद कर सकता है, वही लोकसभा चला भी सकता है। इंडिया गठबंधन को तब तक न लोकसभा जाना चाहिए, न राज्यसभा जब तक कि यह बता न दिया जाए कि माइक बंद किसने किया था, किसकी अनुमति या निर्देश से किया था। परंपरा की बात है तो यह समझना जरूरी है कि विपक्ष के नेता की भी परंपराएं हैं। इस अध्यक्ष को न वे परंपराएं पता हैं, न विपक्ष के नेता का मतलब मालूम है। जिन सांसदों का जन्म ही 10 साल पहले हुआ है, उनकी यह त्रासदी स्वाभाविक है।

देश दुनीया से

समुद्र में कार्बन भंडारण से रुकेगी ग्लोबल वार्मिंग

समुद्र तल पर स्थित बेसाल्ट की चट्टानों के भंडार में कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करने की क्षमता है। ये ज्वालामुखीय चट्टानें हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करने की क्षमता रखती हैं। ये ज्वालामुखीय चट्टानें हमारे वायुमंडल से गर्मी को कैद करने वाली गैस को हटाने में मदद कर सकती हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम समुद्री तटों के निकट फ्लोटिंग रिग बनाना चाहती है। ये रिग समुद्र तल से तेल निकालने के बजाय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रविष्ट करेंगे। अपने स्वयं के विंड टर्बाइनों द्वारा संचालित फ़्लोटिंग प्लेटफार्म आकाश या समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेंगे और उसे समुद्र तल में छिद्रों में पंप करेंगे।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक उत्सर्जित कार्बन को वायुमंडल से हटाने के लिए नए-नए तरीके खोज रहे हैं। कार्बन को ठिकाने लगाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों का ध्यान समुद्र तल की चट्टानों की ओर गया है। समुद्र तल पर स्थित बेसाल्ट की चट्टानों के भंडार में कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करने की क्षमता है। ये ज्वालामुखीय चट्टानें हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करने की क्षमता रखती हैं। ये ज्वालामुखीय चट्टानें हमारे वायुमंडल से गर्मी को कैद करने वाली गैस को हटाने में मदद कर सकती हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम समुद्री तटों के निकट फ्लोटिंग रिग बनाना चाहती है। ये रिग समुद्र तल से तेल निकालने के बजाय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रविष्ट करेंगे। अपने स्वयं के विंड टर्बाइनों द्वारा संचालित फ़्लोटिंग प्लेटफार्म आकाश या समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेंगे और उसे समुद्र तल में छिद्रों में पंप करेंगे। वैज्ञानिक अपनी परियोजना को 'सॉलिड कार्बन' कहते हैं। अगर यह परियोजना उनकी उम्मीद के मुताबिक काम करती है तो तल में प्रविष्ट कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा के लिए समुद्र के तल पर एक चट्टान बन जाएगी। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कनाडा के भूभौतिकीविद् मार्टिन शरवाथ ने कहा कि इससे कार्बन भंडारण बहुत टिकाऊ और सुरक्षित हो जाएगा। इस तकनीक से हमें अन्य भंडारण तकनीकों की तरह कार्बन के वायुमंडल में वापस लौटने और वैश्विक तापमान वृद्धि के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यह अभी तक निश्चित नहीं है कि ये कार्बन हटाने वाली समुद्री फैक्टरियां उम्मीद के मुताबिक काम करेंगी या नहीं। सबसे पहले विज्ञानियों को समुद्र में एक प्रोटोटाइप का परीक्षण करने के लिए लगभग 6 करोड़ डॉलर की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनियाभर में, बेसाल्ट चट्टानें पृथ्वी के समस्त जीवाश्म ईंधन से निकलने वाले कार्बन से ज्यादा कार्बन को स्थायी रूप से जमा कर सकती हैं। गौरतलब है, इस तरह की तकनीक को अपनाने का मतलब यह नहीं कि जीवाश्म ईंधन को अंधाधुंध तरीके से जलाना सुरक्षित है। फिर भी विज्ञानियों का कहना है कि कुछ रिग ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शरवाथ के अनुसार कनाडा के पश्चिमी तट से दूर, वैंकूवर द्वीप के पास कैस्केडिया बेसिन में विश्व के 20 साल के कार्बन उत्सर्जन को कैद करने की गुंजाइश है। यहीं पर विज्ञानी एक फील्ड टेस्ट करना चाहते हैं। यह योजना एक रासायनिक प्रतिक्रिया पर आधारित है जो पहले से ही स्वाभाविक रूप से होती है। बेसाल्ट चट्टान अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है। ऐसी चट्टानें धातुओं से भरी होती हैं जो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेती हैं और कार्बोनेट खनिजों का निर्माण करने के लिए रासायनिक रूप से इसके साथ जुड़ जाती हैं। बेसाल्ट भी टूट जाता है और छिद्रपूर्ण हो जाता है, जिससे नए कार्बोनेट के भरने के लिए पर्याप्त जगह बच जाती है। आइसलैंड में कार्बफिक्स नामक एक परियोजना ने इस प्रक्रिया के एक छोटे संस्करण का सफल प्रदर्शन किया है। इस विधि में पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है। फिर उसे भूमिगत बेसाल्ट चट्टान में इंजेक्ट किया जाता है। ये समुद्री कार्बन-भंडारण कारखाने बहुत महंगे उपक्रम होंगे लेकिन यदि हम पृथ्वी को पूर्व-औद्योगिक तापमान पर वापस लाना चाहते हैं तो हमें अंततः ऐसे मेगा-प्रोजेक्ट का सहारा लेना पड़ सकता है। सॉलिड कार्बन उन बुनियादी तात्कालिक उपायों का विकल्प नहीं है, जिनकी दुनिया भर के जलवायु विशेषज्ञ मांग कर रहे हैं। इन उपायों में जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा में बदलना और खाद्य प्रणालियों के कार्बन उत्सर्जन को कम करना शामिल है। इस बीच, एक अन्य अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ऐसे वायरस खोजे हैं जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वायरस शब्द हमारे मन में खौफ पैदा करता है लेकिन सभी वायरस खौफनाक नहीं होते। इनकी दूसरी भूमिकाएं भी हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड की बर्फ पर विशाल वायरस की मौजूदगी का पता लगाया है जो बर्फ के शैवाल को संक्रमित करके आर्कटिक की बर्फ के काले होने और पिघलने को नियंत्रित कर सकते हैं। वायरस के 'विशाल' से चकित न हों। विशाल होने के बावजूद इन वायरस को कोरी आंख से नहीं देखा जा सकता। अभी माइक्रोस्कोप से भी इन्हें नहीं देखा जा सका है। इनकी खोज नमूनों के डीएनए विश्लेषण से हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन वायरस का उपयोग करके बर्फ के पिघलने की गति को धीमा किया जा सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए एक नया रास्ता मिल सकता है। हर वसंत में आर्कटिक के पिघलने पर जीव-जंतु और काले शैवाल सक्रिय हो जाते हैं। शैवाल के सक्रिय होने से बर्फ पिघलने की गति बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ के तेजी से पिघलने से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए ये वायरस प्राकृतिक समाधान प्रदान करते हैं। आर्कटिक में महीनों के अंधेरे के बाद हर वसंत में जब सूरज उगता है, तो जीवन वापस आ जाता है। ध्रुवीय भालू अपनी सर्दियों की मांद से बाहर निकलते हैं।

आप का नजरीया

पर्यटन की भगदड़ में

इस बार हिमाचल के पर्यटन सीजन से सोशल मीडिया का युद्ध कुछ हलकों में बाहरी सैलानियों खास तौर पर पड़ोसी पंजाब से एक गलत संदेश का वाहक बना रहा। हालांकि इसके बराबर पंजाब के ही कई पोर्टल व डिजीटल मीडिया ने हिमाचल के पक्ष और यहां के सुकून को जिंदा रखा, फिर भी यह मसला कहीं सुलगा जरूर है और एक आर्थिक व सांस्कृतिक टकराव में चंद सिरफिरों को न्यौता दे रहा है। कुछ पहल या ऐसे घटनाक्रम हिमाचल में भी हुए जहां डलहौजी, मकलोडगंज, मनाली व कुछ और स्थल कुख्यात होने लगे हैं। यहां की टैक्सी का साम्राज्य भी 'पर्यटक संबंधों' को सिर्फ एक सीजन को लूटने का जरिया बन गया है, तो सडक़ पर रगड़ खाते ट्रैफिक इंतजाम ने अमन चैन से ही लोहा ले लिया। बेशक पड़ोस से आ रहीं अफवाहें आम नहीं, फिर भी इस तरह के कुप्रचार पर हिमाचल में सामाजिक, सांस्कृतिक व सरकारी चेतना परिलक्षित होनी चाहिए। कम से कम ऐसे दुष्प्रचार का संज्ञान तो लेना होगा, दूसरे यह पर्यटन के मौजूदा हुलिए से रू-ब-रू होने का एक अवसर है ताकि मालूम हो, कौन वास्तविक और कौन शोर शराबा है। हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई फिल्टर नहीं। हमारे प्रवेश द्वार सिर्फ औपचारिक हैं। कम से कम हिमाचल के शांतिप्रिय सफर और पर्यटन के अर्थ की एक आचार संहिता तो लागू की जाए। अगर पर्यटन भीड़ बन रहा है और सरकार इसको केवल पांच करोड़ संख्या के आंकड़े में देख रही है, तो बिगड़ैल परिस्थितियों में हर कोई मौके का फायदा या अवसर की लूट में वर्चस्व की होड़ में शरीक हो जाएगा। यही सब हो भी रहा है। वर्चस्व टैक्सी आपरेटरों से लेकर होटल-रेस्तरां मालिकों तक और यह भी पर्यटन इकाइयों के नाम पर चल रहे धंधे, भीड़ पर्यटन को असामाजिक पर्यटन में बदलते देर नहीं लगाते। पहले चोरी छिपे रेव पार्टियां चलती थीं, लेकिन अब पहाड़ की कंद्राओं तक पहुंचा कारवां कहीं गोवा के नाम पर तो कहीं किसी विदेशी समुद्री तट की तरह अपना आवरण खो रहा है। सर्वप्रथम हिमाचल को यह तय करना है कि इसे किस श्रेणी का पर्यटक चाहिए। यह फैसला गुणात्मक या हाई एंड पर्यटन की खोज में करना है या पांच करोड़ सैलानियों को एक साथ बुलाकर भगदड़ में करना है। आखिर रोहतांग, त्रियूंड या शिकारीदेवी की एक सीमा है। शिमला-मनाली के माल या बिलिंग के टेक ऑफ प्वाइंट की एक गरिमा है। दलाईलामा की नगरी या मिनी लहासा की एक छवि है और जिसे न टैक्सी आपरेटर, होटल-रेस्तरां मालिक या गिफ्ट सेंटर भ्रष्ट या नष्ट कर सकते, लेकिन यहां पूछता कौन है। यहां फ्लाइट या विदेश से पहुंच रहा पर्यटक वैसे ही हांका जा रहा है, जैसे कोई खटारा गाड़ी में आने वाला और मुफ्त के लंगर खाने वाला भीड़ को बढ़ा रहा है। अपने तौर पर हिमाचल को यह तय करना है कि कहां हाई एंड, कहां सांस्कृतिक और कहां भीड़ में पर्यटक को व्यवस्थित करना है। कहां निजी व पर्यटक वाहनों को रोकना और साइट सीईंग टूअर के माध्यम से कैसे आकर्षणों को जोडऩा है। पर्यटन अब व्यवस्था, सही प्रचार और सही छवि के साथ-साथ यह सुनिश्चित भी करना है कि राज्य का चरित्र बदनाम न हो। सारे मंदिरों में देवी दर्शन के लिए फीस और हर डेस्टिनेशन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाए।

गहलोत के 25 लाख के फ्री इलाज को टक्कर देने के लिए भजनलाल ने खेला बड़ा दांव

जयपुर। भजनलाल सरकार के पहले फुल बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा एलान किया गया है। बतौर वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए इस वित्तीय वर्ष के बजट में कुल 27660 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। यह पूरे बजट का 8.26 फीसदी हिस्सा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को ऐतिहासिक योजना के रूप में प्रचारित किया गया था जिसमें 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिए जाने के प्रावधान किए गए थे। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। इसके प्रावधानों में भी जरूरी बदलाव किए गए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान चिरंजीवी योजना में पहले पांच लाख, फिर दस लाख और बाद में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किए जाने के प्रावधान किए गए थे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत चिरंजीवी योजना को देश की नंबर वन योजना बता रहे थे। भाजपा ने इस योजना को सीरे से नकार दिया था। इस योजना में कई तरह की खामिया बताई गई थी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह यहां तक कह चुके हैं कि 25 लाख रुपए के मुफ्त इलाज का सिर्फ दावा था। हकीकत में प्रदेश के एक भी मरीज को 25 लाख रुपए का इलाज नहीं मिला। आंकड़ों को देखें तो सर्वाधिक साढ़े 13 लाख रुपए का इलाज सिर्फ एक मरीज का किया गया। करीब चार या पांच मरीज ऐसे हैं जिन्हें पांच से सात लाख रुपए का इलाज लिया। शेष सभी इलाज दो से तीन लाख रुपए से कम ही रहे। ऐसे में 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज केवल दिखावा था। राज्य के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तो इसे सदी की सबसे अव्यवहारिक, अलोकतांत्रिक और असफल योजना योजना करार दिया था।

जालंधर पश्चिमी क्षेत्र में उपचुनाव में 11 बजे तक 23.04 फीसदी मतदान

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब के जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान सुबह से चल रहा है। यहां दिन के 11 बजे तक 23.04 फीसदी मतदान हुआ है। जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर एक लाख 71 हजार 963 मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग ने पूरे क्षेत्र में 181 मतदान केंद्र बनाए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के सात सौ जवान तैनात किए गए हैं। इस सीट पर आप के पूर्व विधायक शीतल अंगुराल अब भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ भाजपा के पूर्व मंत्री भगत चुन्नी लाल के पुत्र महिंदर भगत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसी सीट पर कांग्रेस से पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर सुरिंदर कौर, अकाली दल से सुरजीत कौर तथा बसपा की तरफ से बिंदर लाखा चुनाव मैदान में हैं।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश एक सप्ताह में खोला जाए शंभू बॉर्डर

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब एवं ने हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह आदेश दिए हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि हरियाणा सरकार एक हफ्ते में रोड क्लियर करे और वहां से बैरिकेड हटाए। हाईकोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है और इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर वे शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा देते हैं तो फिर किसान अंबाला में घुस जाएंगे और एस पी ऑफिस का घेराव करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसानों को हरियाणा में घुसने या घेराव करने से नहीं रोका जा सकता। उल्लेखनीय है कि शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद चल रहा है और पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बारे में किसान नेता मनजीत राय ने कहा कि हमें अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली, लेकिन इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बार-बार पूछ रहे हैं कि किस संविधान और कानून के तहत सड़क पर दीवारें बनाई गई। सरकार ने लोकतंत्र को दरकिनार कर यह सड़कें बंद की थी। यह आम जनता, किसानों और व्यापारियों की राजधानी जाने की भावनाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि हम यहां नहीं बैठना चाहते, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हम इस बारे में मीटिंग कर अगली रणनीति तय करेंगे और अगले संघर्ष का एलान करेंगे।

राजनीति से प्रेरित है हाथरस दुर्घटना की एसआईटी रिपोर्ट : मायावती

लखनऊ (हिंस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने हाथरस दुर्घटना में प्रस्तुत एसआईटी रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित होना बताया है। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में बीते दिनों हुए सत्संग में मची भगदड़ में 121 निर्दोष की जान चली गई थी। दुर्घटना में महिलाओं, बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता-जागता प्रमाण है। किंतु एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है, यह अति-दु:खद है। उन्होंने कहा कि इस अति-जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के सम्बंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंताओं का कारण बना हुआ है। साथ ही, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के बजाए उसे क्लीनचिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो। मायावती ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस और टैंकर की जोरदार भिड़ंत में दो महिलाओं व एक बच्चे सहित 18 लोगों की मौत पर दु:ख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसे में हुई लोगों की मौत तथा लगभग 20 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना अति-दु:खद है। मेरी गहरी संवेदना। ऐसी दुर्घटनाओं में लोगों की मौतों को रोकने के उपाय जरूर किए जाएं।

अफसर कर रहे हैं *मंत्रियों की जासूसी*, गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान ने मचाई राजस्थान पॉलिटिक्स में खलबली

जयपुर। राजस्थान में सरकार पर ब्यूरोक्रेसी के हावी रहने के आरोप तो कई बार लगे लेकिन कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने अब एक गंभीर आरोप और लगा दिया है। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए पीसीस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के अफसर मंत्रियों की जासूसी कर रहे हैं। मंत्रियों के पास कौन सी फाइल जा रही है। मंत्री क्या काम करने वाले है। इन सभी गतिविधियों की जानकारी गुपचुप तरीके से दिल्ली तक पहुंचाई जा रही है। डोटासरा ने कहा कि यह प्रजातंत्र का घोर अपमान है। अपने विभाग का काम करने के लिए मंत्री स्वतंत्र होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। कई मंत्री तो इस्तीफा लिए हुए घूम रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि सभी मंत्रियों के स्पेशल असिस्टेंट लगाए जाते हैं तो मंत्री के विश्वासपात्र होते हैं और सभी तरह के कार्यों की जानकारी उन्हें होती है। इस सरकार में स्पेशल असिस्टेंट मंत्रियों की इच्छा अनुसार नहीं लगाए गए। मंत्री चाहकर भी उनसे बात नहीं करना चाहते लेकिन एसए होने के नाते वह हर कामकाज की जानकारी जुटा लेते हैं। डोटासरा के मुताबिक यही अफसर मंत्रियों की जासूसी कर रहे हैं। मंत्रियों के स्पेशल असिस्टेंट अपनी रिपोर्ट ब्यूरोक्रेसी के चीफ यानी मुख्य सचिव तक भेजते हैं और वे उसे दिल्ली भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद स्थिति है। मंत्री खुद डरे हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मौजूदा सरकार की स्थिति असमंजस सी बनी हुई है। कोई मंत्री इस्तीफा दे देता है और उस इस्तीफे को 20 से 25 दिन तक छुपाए रखता है। इस्तीफा दिए हुए कई दिन बीत गए लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं। खुद इस्तीफा देने वाले मंत्री को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। डोटासरा ने कहा कि सरकार में मंत्रियों को कोई नहीं पूछ रहा। बजट में कृषि संबंधित कितने प्रस्ताव शामिल किए गए। इसकी जानकारी खुद कृषि मंत्री को भी नहीं है। अफसरों ने कृषि मंत्री से बात तक नहीं की।

कृषि मंत्री को घर के रसोई से कोई लेना देना नहीं : महिला प्रकोष्ठ

देवरिया (हिंस)। जनपद देवरिया में अपने घर में ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की किरकिरी हो रही है। कृषि मंत्री के दाल पर दिये बयान से समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ ने आड़े हाथों लिया है। महिला प्रकोष्ठ की नेत्रियों ने कृषि मंत्री के बयान पर कहा कि इस प्रकार के बयान देने से मालूम पड़ता है, उन्हें घर के रसाई से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की नेत्री अलका सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया है, जो महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उनके मीडिया से बातचीत के दौरान दाल का गलत रेट बताने से उनकी वास्तविकता की जानकारी हो गयी है। किसान से घर की रसाई चलाने वाली महिलाओं तक दाल की कीमत की जानकारी हर किसी को है। सिर्फ कृषि मंत्री ही सही दाम नहीं जानते है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के अतिरिक्त समाज में हर वर्ग की महिलाओं में कृषि मंत्री के बयान को लेकर असंतोष का वातावरण व्याप्त है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को अपने बयान के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। वहीं महिलाएं उन्हें माफ नहीं करने वाली है।

राजस्थान को विकास के नए पथ पर ले जाने वाला बजट : शेखावत

जयपुर (हिंस)। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सर्वसमावेशी विकास का बजट प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी को शुभकमानाएं दीं। अपनी प्रतिक्रिया में शेखावत ने कहा कि भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट हर वर्ग के सपने पूरे होने की गारंटी है। अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान को विकास के नए पथ पर लेकर जाएगी। इस बजट के माध्यम से राजस्थान देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। शेखावत ने कहा कि भजनलाल सरकार के बजट के दायरे से कोई छूटा नहीं है। हर वर्ग को यह बजट अपने लिए लगेगा और हर वर्ग स्वयं को सशक्त महसूस करेगा। नारी शक्ति, अन्नदाता, युवाओं और गरीबों का बजट में विशेष ख्याल रखा गया है। पांच साल में चार लाख नौकरियों से युवा सशक्त होगा। ब्याज मुक्त लोन देने के अलावा किसानों के लिए कई घोषणाएं बताई हैं कि भाजपा सरकार किसानों की हितैषी है। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने से हमारी माताएं-बहनें का सशक्तीकरण होगा। साथ ही, महंगाई से राहत देने के लिए कई ठोस कदम बजट में उठाए गए हैं। पर्यटन और संस्कृति की चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि पर्यटन व संस्कृति के सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से वित्त मंत्री ने विजन शानदार प्रस्तुत किया है। राज्य में 20 लाख परिवारों को पर्यटन से रोजगार मिलता है। राजस्थान की नई पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड और राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनाने की घोषणा स्वागत योग्य है। पर्यटन और संस्कृति पर पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा व्यय करने से राजस्थान में पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र खाटू श्याम जी मंदिर का काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने समेत धार्मिक स्थलों के विकास की घोषणाएं सराहनीय है और इनका हृदय से स्वागत है।

परमिट जारी करने की बजाए सरकारी बसें बढ़ाए सरकार : कुमारी सैलजा

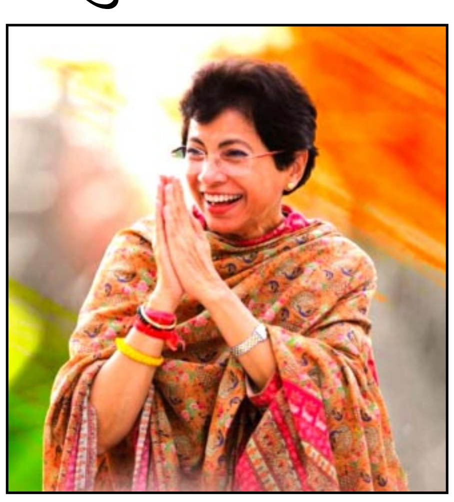

सिरसा (हिंस)। प्रदेश की भाजपा सरकार प्राइवेट बसों के परमिट जारी कर हरियाणा रोडवेज को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। निजी हाथों में देते ही सरकारी महकमे परिवहन विभाग को राज्य सरकार बंद कर देगी। सार्वजनिक परिवहन सेवा की हरियाणा रोडवेज को भाजपा सरकार जिंदा रखना चाहती है तो फिर उसे स्टैट कैरिज बसों के परमिट जारी करने की बजाए सरकारी बसों की खरीद कर रोडवेज के बेड़े को बढ़ाना चाहिए। मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार के आदेश पर परिवहन विभाग ने स्टैट कैरिज बसों के परमिट को लेकर नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे व मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर पड़ने वाले 362 रूटों के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। यही नहीं, किसी भी रूट पर स्टैट कैरिज बसों के परमिट 50 प्रतिशत तक करने का एलान किया है। यानी, आधे रूटों पर निजी क्षेत्र की बसें संचालित होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह रोडवेज का निजीकरण दिशा में शुरुआती कदम है। धीरे-धीरे परमिट वाली बसों की संख्या को बढ़ाकर 50 प्रतिशत से अधिक कर दिया जाएगा और फिर एक दिन रोडवेज को बंद करने या पूरी तरह निजीकरण करने का फरमान सुना दिया जाएगा। रोडवेज के निजीकरण का शुरू से कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी किसी तरह की सुनवाई प्रदेश सरकार नहीं कर रही। कुमारी सैलजा ने कहा कि पीएसी की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि सरकारी लापरवाही व दिलचस्पी न लेने के कारण हरियाणा रोडवेज घाटे में है। नई बसें न होने व लचर प्रबंधन के कारण ही रोडवेज की बसें अपने लक्ष्य से कम दौड़ रही हैं। साल 2015-16 में प्रति किलोमीटर घाटा 10.61 रुपए था, जो 05 साल में ब ?कर 23.62 रुपए हो चुका है। जबकि, डीजल खर्च भी अनुमान के मुकाबले 39.86 लाख लीटर अधिक रहा। इसी तरह ब्रेकडाउन भी बार-बार होता रहा, जिससे बसें लक्ष्य के मुकाबले 07 करोड़ किलोमीटर कम दौड़ सकी।

जनता को राहत नहीं, विकास का रोडमैप गायब : गहलोत

जयपुर (हिंस)। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आज राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए बजट का शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं लगता है। इस बजट से ना जनता को राहत मिली है और ना ही कोई विकास का रोडमैप बन रहा है। गहलोत बुधवार को वित्त मंत्र दीया कुमारी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत राजस्थान बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मिशन 2030 के तहत राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा था। मुझे आशा थी कि हमारी सरकार जाने के बाद भाजपा सरकार कम से कम राजस्थान की बेहतरी के लिए इस मिशन को ध्यान में रखकर काम करेगी और विकास की बेहतरीन योजनाएं लाएगी। आज राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए बजट का शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं लगता है। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में चलाई गईं योजनाओं एवं किए गए कामों में कमी बजट के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रही है। इस बजट से ना जनता को राहत मिली है और ना ही कोई विकास का रोडमैप बन रहा है। पिछले 10 साल से जैसा केंद्र सरकार का बजट नीरस एवं दिशाहीन होता है वैसे ही आज राजस्थान सरकार का बजट भी नीरस और दिशाहीन आया है। जनता को उम्मीद थी कि मोदीजी की गारंटी के मुताबिक पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम की जाएंगी परंतु ऐसा नहीं किया गया। बल्कि हमारी सरकार की महंगाई से राहत देने वाली योजनाओं जैसे 100 यूनिट फ्री बिजली, अन्नपूर्णा राशन किट, इन्दिरा रसोई, फ्री कृषि बिजली आदि के लिए कोई बजट आंवटन नहीं किया है यानी आने वाले दिनों में जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बजट के दिन ही रोडवेज एसी बसों का किराया 10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाकर सरकार ने अपना उद्देश्य जाहिर कर दिया है। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट में नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की डीपीआर बनाने की घोषणा कर वाहवाही लेने का प्रयास किया है। हमारी सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपए सड़कों के लिए देती थी जिसे इस सरकार ने 5 करोड़ रुपए कर दिया है। यह दिखाता है कि ये सरकार काम में नहीं सिर्फ पैकेजिंग में भरोसा करती है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि 25 लाख रुपए राशि वाली चिरंजीवी बीमा योजना की जगह पर ये सरकार 5 लाख रुपए राशि की आयुष्मान भारत योजना को लागू करना चाहती है। चिरंजीवी योजना में राजस्थान का प्रत्येक परिवार कवर था पर आयुष्मान भारत में प्रदेश की 50 प्रतिशत आबादी भी शामिल नहीं होगी। चिरंजीवी योजना में बड़ी संख्या में अस्पताल शामिल थे पर आयुष्मान योजना में अस्पतालों की संख्या बेहद कम है। ओपीएस को लेकर भी सरकार की कोई राय बजट में नहीं आई है।

फतेहपुर में स्नान करने गए तीन बच्चों की तालाब में डूबकर मौत

फतेहपुर (हिंस)। जनपद के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को तालाब में स्नान करने गए तीन बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस नें उन शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के जनता गांव निवासी गोरेलाल का पुत्र विष्णु (07), आयुष (08) और अंश (09) गांव के ही पास स्थित एक तालाब में स्नान करने गए थे। तालाब में नहाते समय गहरे पानी में तीनों चले गए और डूबने लगे। शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। गांव के ही टिंकू ने तालाब में उतरकर बच्चों को बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से सीएचसी पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी।

सोनीपत में भाजपा का बड़ा दांव : कांग्रेस के मेयर भाजपा में होंगे शामिल

सोनीपत (हिंस)। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। भाजपा ने मोहन लाल बडौली को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपने के साथ ही सोनीपत में खेला कर दिया है। गुरुवार को सोनीपत के पहले मेयर निखिल मदान दिल्ली में भाजपा में शामिल होने की खबर है। सोनीपत, जिसे कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। यहां कांग्रेस का ही विधायक है और स्थानीय राजनीति में कांग्रेस का दबदबा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से हार मिली थी। अब भाजपा के निशाने पर है। वर्ष 2020 में सोनीपत नगर निगम के पहले चुनाव में निखिल मदान ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर भाजपा के ललित बत्रा को 13,817 वोट से हराकर सोनीपत के पहले मेयर बने थे। अब राजनीति गलियारों में चर्चा है कि निखिल मदान अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में भाजपा के कई बड़े नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में शामिल होंगे। वे भारी दल-बल के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी इस संबंध में औपचारिक घोषणा नहीं की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के प्रयास से मदान भाजपा में शामिल होते हैं तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। निखिल मदान का भाजपा में शामिल होना भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिससे वे कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल मदान पंजाबी नेता हैं और इस कदम से भाजपा पंजाबी वोटरों को साधने का प्रयास करेगी। भूपेंद्र हुड्डा के लिए यह खबर निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि इससे उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, सोनीपत के राई हलके के विधायक मोहन लाल बड़ौली को भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाना भी भाजपा की इस क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। इस कदम से सोनीपत की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आने की संभावना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस चुनौती का सामना कैसे करती है।

मुहर्रम एवं श्रावणी मेला को लेकर मुख्य सचिव ने जिला पदाधिकारी के साथ की समीक्षात्मक बैठक

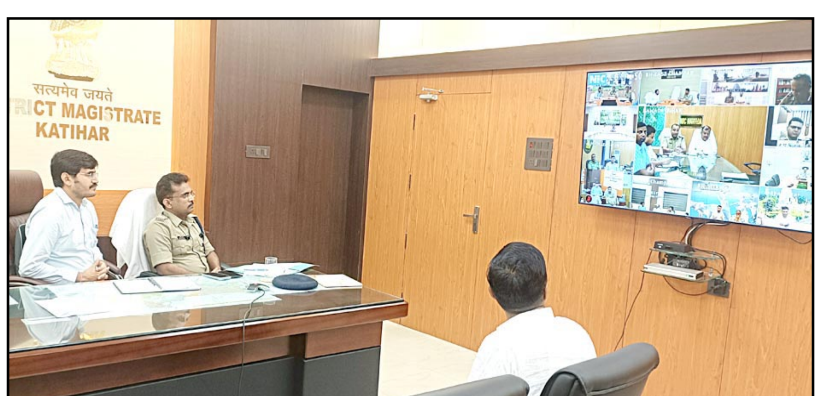

कटिहार (हिंस)। मुहर्रम पर्व एवं श्रावणी मेला के अवसर पर जिले में विधि व्यवस्था को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव ने बुधवार को जिला पदाधिकारी के साथ विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार मौजूद थे। उक्त बैठक में मुख्य सचिव ने मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर जिले में दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की उपलब्धता, मोहर्रम जुलूस का आयोजन हेतु रूट का निर्धारण, जुलूस हेतु लाईसेंस की स्वीकृति, कर्बला की मैदान व विवादित स्थल एवं क्षेत्रों का निरीक्षण, ताजिया जूलुस हेतु मार्ग व स्थान का निर्धारण, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्युत आपूर्ति, शहरी व विवादित क्षेत्रों में ड्रॉन के माध्यम से रुट का सत्यापन, विवादित स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण, मोहर्रम के अवसर पर एंबुलेंस एवं मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्त, किसी भी अप्रिय घटना व अफवाहें के रोकथाम हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का निगरानी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विगत कई वर्षों में उत्पन्न विवाद में संलिप्त व्यक्तियों का सत्यापन कराने, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में घटित छोटे-छोटे आपसी विवाद की जानकारी प्राप्त कर चिन्हित करने, चिन्हित व संवेदनशील विवादित स्थल एवं क्षेत्रों का स्वयं निरीक्षण करने, निर्वाचन के समय चिन्हित साम्प्रदायिक क्षेत्रों में होने वाले सभी गतिविधियों एवं संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने, मोहर्रम के अवसर पर चिन्हित असामाजिक एवं उपद्रवियों पर कड़ी नजर रखने सहित आपत्तिजनक पोस्ट के रोकथाम हेतु सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया।

अदाणी समूह से जमीन वापस लेने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली ।
गुजरात हाईकोर्ट ने अदाणी समूह से 108 हेक्टेयर चारागाह जमीन वापस लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। गुजरात हाईकोर्ट ने अदाणी समूह से 108 हेक्टेयर चारागाह जमीन वापस लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मुंद्रा बंदरगाह के पास 2005 में अदाणी समूह की कंपनी को यह गौचर भूमि दे दी गई थी।

5 जुलाई को राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि वे लगभग 108 हेक्टेयर गौचर भूमि अदाणी समूह की इकाई से वापस लेगी। जो कि 2005 में उन्हें दी गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि गुजरात राज्य के राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के हलफनामे पर ध्यान देते हुए, हम संबंधित प्राधिकरण से कानून के अनुसार पुन: अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की अपील पर गौर किया कि न्याय के हित में विवादित आदेश पर रोक लगाना जरूरी है। पीठ ने कहा, नोटिस जारी करें। विवादित आदेश पर रोक लगाएं।

क्या था मामला

दरअसल, 2005 में गुजरात के राजस्व विभाग ने अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड को 231 एकड़ गौचर भूमि आवंटित की थी। लेकिन ग्रामीणों को भूमि आवंटित होनी की सूचना 2010 में पता चली। जब एपीएसईजेड ने गौचर भूमि पर बाड़ लगाना शुरू किया। गांव के निवासियों ने अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड को 231 एकड़ गौचर भूमि आवंटित करने के निर्णय के खिलाफ एक जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट का रुख किया था। 2014 में राज्य सरकार ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर ने चरागाह के उद्देश्य से अतिरिक्त 387 हेक्टेयर सरकारी भूमि देने का आदेश पारित किया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया था।

न्यूज ब्रीफ

भारत के छोटे शहरों में अब 65 प्रतिशत लेनदेन डिजिटल, इसमें भी जेन एक्स सबसे आगे

मुंबई । भारत के छोटे शहरों में अब 65 प्रतिशत लेनदेन डिजिटल से किया जा रहा है। किर्नी इंडिया और अमेजन पे इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल भुगतान क्रांति का नेतृत्व भारत के सहस्राब्दी (25-43 वर्ष की आयु) और जेन एक्स (44-59 वर्ष की आयु) द्वारा किया जा रहा है। बूमर्स (60 वर्ष और उससे अधिक) के पास युवा समूहों की तुलना में अधिक कार्ड और ई-वॉलेट का उपयोग किया जाता है। भारत के छोटे शहरों में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर अमेजन पे ने एक रिपोर्ट पेश की है जिससे पता चला कि भारत के छोटे शहरों में उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 65 प्रतिशत लेनदेन अब डिजिटल हो रहा है, जबकि बड़े शहरों में यह अनुपात लगभग 75 प्रतिशत है। किर्नी इंडिया और अमेजन पे इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल भुगतान में क्रांती आई है, जिसका नेतृत्व भारत के सहस्राब्दी (25-43 वर्ष की आयु) और जेन एक्स (44-59 वर्ष की आयु) द्वारा किया जा रहा है। पार्टनर, फाइनेंशियल सर्विसेस लीड, किर्नी इंडिया की शाश्वत शर्मा, ने कहा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेनदेन में युवा डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने से लेकर बीएनपीएल (अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें) जैसी उभरती भुगतान ट्रेंड को लेकर भारत में भुगतान का परिदृश्य बदल रहा है। लेन-देन हुआ आसान उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट 120 शहरों, 6,000 से अधिक उपभोक्ताओं और 1,000 व्यापारियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, नकद लेनदेन कम होने के कारण यूपीआई, डिजिटल वॉलेट और कार्ड का व्यापक आकर्षण बढ़ रहा है, जिसमें 69 प्रतिशत व्यापारिक लेनदेन डिजिटल मोड से हो रहे हैं। अमेजॉन पे इंडिया के सीईओ विकास बंसल ने कहा, भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति क्षेत्रों में हो रही है, जो उपभोक्ताओं और व्यापारियों द्वारा समान रूप से प्रेरित है। सड़क विक्रेताओं और छोटे शहरों में भी डिजिटल लेनदेन के प्रवेश के साथ, हम अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। अमेजन पे इस बदलाव में सबसे आगे रहने और सभी क्षेत्रों में भारतीयों को यह सुविधा देना चाहता है।

टाटा समूह के सूर्य कांत यूएसआईएसपीएफ के निदेशक मंडल में हुए शामिल, बोले- मैं साथ काम करने के लिए उत्साहित

US·INDIA STRATEGIC PARTNERSHIP FORUM

नई दिल्ली । भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र के दिग्गज एवं टाटा संस के वरिष्ठ सलाहकार सूर्य कांत यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मुकेश अघी ने कहा कि सूर्य कांत का नेतृत्व रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने में मददगार साबित होगा। मुकेश अघी ने कहा, सूर्य कांत का नेतृत्व रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने और उसका मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। अमेरिका और भारत के बीच मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और एसटीईएम शिक्षा की बदलती गतिशीलता को वह समझते हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे यकीन है कि अपने इनपुट और विशेषज्ञयता के साथ वह नए रास्ते तराशेंगे। इसके साथ अमेरिका और भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने में भूमिका निभाएंगे। सूर्य कांत के भारत में आईटी क्षेत्र के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए जाना जाता है। सूर्य कांत ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं।

सोना और चांदी खरीदना हुआ महंगा सोना 72,550 और चांदी लगभग 93,200 रुपए

नई दिल्ली । सोने और चांदी के वायदा कारोबार में तेजी देखी जा रही है। दोनों के वायदा भाव तेजी के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 72,550 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 93,200 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वैश्विक बाजार में भी सोने व चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रेक्ट 132 रुपये की तेजी के साथ 72,530 रुपये के भाव पर खुला। इसके बाद यह 157 रुपये की तेजी के साथ 72,555 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरूआत तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रेक्ट 104 रुपये की तेजी के साथ 93,073 रुपये पर खुला। जो कुछ समय बाद 217 रुपये की तेजी के साथ 93,186 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था।

सब्जियों की कीमत बढ़ने से खुदरा महंगाई में होगी वृद्धि भीषण गर्मी के बाद बारिश से फसलों को नुकसान

नई दिल्ली ।
पहले भीषण गर्मी और अब बारिश की वजह से टमाटर, आलू और प्याज सहित हरी सब्जियों की कीमतें बढ़ने का सीधा असर जून की खुदरा महंगाई पर दिख सकता है। अनुमान है कि 12 जुलाई को जारी होने वाली जून की महंगाई दर 4.80 फीसदी रह सकती है जो मई में 4.75 फीसदी रही थी। 54 अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, महंगाई दर 4.10 फीसदी से लेकर 5.19 फीसदी तक रह सकती है। भीषण गर्मी, फिर बारिश से उत्तरी भारत में कृषि का नुकसान हुआ था। इससे टमाटर, आलू और प्याज की कीमतें 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ी थीं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य आर्थिक सलाहकार कनिका पसरीचा ने कहा, अनाज और दालों के साथ सब्जियों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने खाद्य मुद्रास्फीति को उच्च स्तर पर बनाए रखा। इससे अंडे, फलों और मसालों की कम कीमतों का असर भी खत्म हो गया। और ज्यादा बढ़ सकते हैं टमाटर, आलू व हरी सब्जियों के दाम आने वाले समय में टमाटर, आलू और हरी सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में बारिश से फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों का कहना है कि मुरादाबाद क्षेत्र में फसलें सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। किसानों ने बताया, टमाटर के खेतों में पानी भर जाने से पौधे सड़ रहे हैं। इससे किसान अन्य फसलों की खेती के लिए टमाटर की फसल उखाड़ रहे हैं। इससे पहले भीषण गर्मी से फसलें बर्बाद हुई थीं। किसानों का कहना है कि गर्मी में उन्हें टमाटर की सही कीमतें नहीं मिली थीं। अब जब कीमतें अच्छी हैं तो बारिश ने उस पर पानी फेर दिया। दूरसंचार कंपनियों के टैरिफ बढ़ाने का भी दिखेगा असर कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि इस महीने से टेलीकॉम कंपनियों की 25 फीसदी तक टैरिफ बढ़ोतरी से आने वाले महीनों में महंगाई पर कम से कम 0.2 फीसदी तक दबाव बढ़ने की संभावना है। 19 अर्थशास्त्रियों के अनुसार, मुख्य मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुएं शामिल नहीं हैं जून में 3.10 फीसदी रह सकती है।

खादी एवं ग्रामोद्योग ने दिए10 लाख से अधिक रोजगार, पहली बार सालाना कारोबार 1.50 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

नई दिल्ली । खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा, रोजगार में वृद्धि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया। उन्होंने कहा, 2013-14 के बाद से 10 वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग गतिविधियों में नए रोजगार का सृजन 81 फीसदी बढ़ गया। खादी एवं ग्रामोद्योग का सालाना कारोबार 2023-24 में पहली बार 1.50 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया इस दौरान इसने 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिए। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा, रोजगार में वृद्धि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया। उन्होंने कहा, 2013-14 के बाद से 10 वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग गतिविधियों में नए रोजगार का सृजन 81 फीसदी बढ़ गया। इस अवधि में उत्पादन 315 फीसदी और खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में 400 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2024-25 में 23,100 करोड़ रुपये का होगा गेमिंग उद्योग भारतीय गेमिंग उद्योग चालू वित्त वर्ष में 20 प्रतिशत बढ़कर 23,100 करोड़ रुपये का हो सकता है। ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या चीन से आगे निकलकर 44.2 करोड़ पहुंच गई है। रिपोर्ट में गेमिंग उद्योग के लिए व्यापक आचार संहिता की वकालत की गई, जो जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नैतिक व्यवहार के मानक निर्धारित करती हो।

एलपीजी के ई-केवाईसी को लेकर केंद्र सरकार का वीडी सतीसन को जवाब, कहा इससे फर्जी ग्राहकों पर लगेगी लगाम

नई दिल्ली ।
भारत में तेल का व्यापार करने वाली कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी नियम को लागू किया है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि फर्जी ग्राहकों की पहचान करने के लिए ई-केवाईसी प्रणाली को लागू किया गया है। दरअसल, कई बार फर्जी खाते से घरेलू गैस सिलेंडर को बुक किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे फर्जी खातों को खत्म करने और घरेलू गैस सिलेंडरों की फर्जी बुकिंग पर लगाम लगाने के लिए, तेल का व्यापार करने वाली कंपनियों ने ई-केवाईसी प्रणाली को लागू किया है। हरदीप पुरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ई-केवाईसी प्रणाली के लिए तेल कंपनियों और केंद्र सरकार की ओर से कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। वीडी सतीसन ने क्या कहा था दरअसल, इससे पहले केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीसन ने इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा था कि ई-केवाईसी प्रणाली की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सतीसन ने इसे लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी को पत्र भेजा था। पत्र में अनुरोध किया गया है कि इस असुविधा को दूर करें। अब केंद्रीय मंत्री ने सतीसन के पत्र का जवाब दिया है। घर बैठे आसानी से करवा सकते हैं ई-केवाईसी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फर्जी खातों का पता लगाने के लिए ई-केवाईसी नियम को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली के तहत बीते आठ महीने से काम किया जा रहा है और इसके लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। गैस सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भी ई-केवाईसी प्रणाली को लागू किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ग्राहकों को ई-केवाईसी के लिए गैस एजेंसी तक जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक घर बैठे आसानी से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए आपके घर पर सिलेंडर पहुंचाने वाले गैस कंपनी के के कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से आपके आधार नंबर की तस्वीर लेंगे। इसके बाद ग्राहक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।

एसआईपी में निवेश बढ़कर 21,262 करोड़ रुपये की नई ऊंचाई पर, जून में 55 लाख एकाउंट खुले

नई दिल्ली ।
जून महीने में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए रिकॉर्ड 21,262 करोड़ का निवेश किया गया है। इस तरह से अब एसआईपी के जरिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) भी बढ़कर 12.43 लाख करोड़ रुपये पहुंच गईं। म्यूचुअल फंड निवेशकों ने जून, 2024 में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में रिकॉर्ड 21,262 करोड़ रुपये का निवेश किया। यह लगातार 12वां महीना है, जब एसआईपी में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। मई में यह आंकड़ा 20,904 करोड़ था। बाजार में तेजी और नए निवेश प्रवाह के दम पर एसआईपी के तहत प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) भी बढ़कर 12.43 लाख करोड़ रुपये पहुंच गईं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश 17 फीसदी बढ़कर 40,608 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। मई, 2024 में यह आंकड़ा 34,697 करोड़ रुपये था। 27 महीने में सबसे ज्यादा आया निवेश पिछले महीने मल्टीकैप में निवेश बढ़कर 27 महीने के उच्च स्तर 4,709 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, म्यूचुअल फंड योजनाओं में सेक्टोरल या थीमैटिक फंड्स में लगातार दूसरे महीने सर्वाधिक निवेश देखने को मिला। जून में इनमें 22,352 करोड़ रुपये का निवेश आया। जबकि लार्जकैप में निवेश 46 फीसदी बढ़कर तीन माह के उच्च स्तर 970 करोड़ रुपये पहुंचा। वहीं स्मॉलकैप में निवेश 16 फीसदी बढ़कर 2,260 करोड़ और मिडकैप में तीन फीसदी बढ़कर 2,528 करोड़ रुपये पहुंचा।

187 करोड़ के अवैध पैसे ट्रांसफर केस में ईडी का छापा, पूर्व मंत्री-कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर छापे

बंगलूरू ।
कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दाल जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने सरकारी निगम से जुड़े अवैध धन हस्तांतरण मामले में छापेमारी की। कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दाल जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने सरकारी निगम से जुड़े अवैध धन हस्तांतरण मामले में छापेमारी की। इस मामलों में अबतक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 187 करोड़ रुपये के अवैध हस्तांतरण पर ईडी जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कथित वाल्मीकि निगम घोटाले में पूर्व मंत्री बी नागेंद्र से जुड़े आवासीय और आधिकारिक परिसरों पर छापेमारी की। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास बोर्ड के अध्यक्ष बसनगौड़ा दद्दाल के रायचूर आवास पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा धन के अवैध हस्तांतरण के संबंध में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है। बेंगलुरू में ईडी के अधिकारियों ने तीन स्थानों पर छापेमारी की। ईडी ने हैदराबाद में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दाल से कथित तौर पर जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी एक सरकारी निगम से जुड़े अवैध धन हस्तांतरण मामले के तहत की गई। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के बैंक खातों से 187 करोड़ रुपये के कथित अनाधिकृत हस्तांतरण की जांच चल रही है। इसके तहत बंगलूरू, रायचूर और बेल्लारी में छापेमारी की गई।

2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करेंगे भारत-रूस, बढ़ाएंगे निवेश

नई दिल्ली ।
भारत और रूस ने निवेश को पुनर्जीवित करके, व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके और ऊर्जा से लेकर कृषि और बुनियादी ढांचे तक के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद साझा बयान

मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 22वें वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में, दोनों पक्षों ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराई और रूस-भारत व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय बातचीत को गहरा करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का संकल्प लिया।

इन नौ प्रमुख क्षेत्रों पर बनी सहमति

दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए नौ प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की, जिनमें व्यापार, राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार निपटान, उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे जैसे नए मार्गों के माध्यम से कार्गो कारोबार में वृद्धि, कृषि उत्पादों, खाद्य और उर्वरक में व्यापार की मात्रा में बढ़ोत्तरी, परमाणु ऊर्जा समेत ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को गहरा करना, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बातचीत को मजबूत करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश और संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देना, दवाओं की आपूर्ति पर सहयोग करना और मानवीय सहयोग का विकास शामिल हैं।

100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार पर सहमति

इस दोनों राष्ट्रप्रमुखों ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को समाप्त करने और ईएईयू-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की संभावना समेत द्विपक्षीय व्यापार के उदारीकरण के क्षेत्र में बातचीत जारी रखने की आकांक्षा पर सहमति व्यक्त की। बता दें कि इसका उद्देश्य साल 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की पारस्परिक रूप से सहमत व्यापार मात्रा प्राप्त करना है, जिसमें संतुलित द्विपक्षीय व्यापार प्राप्त करने के लिए भारत से माल की आपूर्ति में वृद्धि शामिल है। इसके साथ ही, विशेष निवेश व्यवस्थाओं के ढांचे के भीतर निवेश गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने पर सहमति व्यक्त की गई।

भारतीय रूपये में हो सकती है कच्चे तेल की खरीद

वहीं इस दौरान संयुक्त बयान में कहा गया कि वे राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके द्विपक्षीय निपटान प्रणाली के विकास पर सहमत हुए। इसका मतलब यह है कि भारत की तरफ से रूस से कच्चे तेल जैसी किसी भी खरीद का भुगतान संभावित रूप से भारतीय रुपये में किया जा सकता है। इसके बाद रूस की तरफ से भारत से आयात के भुगतान के लिए इस मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत रूसी रूबल का उपयोग भी संभव है।

परमाणु ऊर्जा, कृषि, पशु चिकित्सा समझौते में शामिल

दोनों नेताओं ने कहा कि वे कृषि उत्पादों, खाद्य और उर्वरकों में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा बढ़ाने के साथ-साथ पशु चिकित्सा, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी प्रतिबंधों और निषेधों को हटाने के उद्देश्य से गहन संवाद बनाए रखने के पक्ष में थे। जबकि परमाणु ऊर्जा, तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल्स समेत प्रमुख ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग का विकास और ऊर्जा बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी के विस्तारित रूप भी समझौते का हिस्सा थे।

तमाम क्षेत्रों में निरंतर विस्तार के पक्ष में दोनों देश

इस दौरान संयुक्त बयान में डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान और अनुसंधान, शैक्षिक आदान-प्रदान और उच्च तकनीक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए इंटर्नशिप के कई क्षेत्रों में निवेश और संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने अनुकूल राजकोषीय व्यवस्था प्रदान करके नई संयुक्त (सहायक) कंपनियों के निर्माण की सुविधा के लिए भी सहमति जताई। दोनों पक्ष ने मानवीय सहयोग विकसित करने, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, खेल, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में परस्पर संपर्क के निरंतर विस्तार के पक्ष में थे। भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर रूस सहमत वहीं इस शिखर सम्मेलन के दौरान रूस ने भारत में संयुक्त उत्पादन सुविधाएं स्थापित करके रूसी मूल के सैन्य प्लेटफार्मों के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में देरी पर भारत की चिंताओं को दूर करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर वार्ता में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आपूर्ति में देरी का मुद्दा उठाया था।

मेदवेदेव ने सिनर से बदला लिया, पाओलिनी ने इटली के लिए रचा इतिहास

नई दिल्ली।
पांचवीं वरीयता प्राप्त दानिल मेदवेदेव ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जानिक सिनर को विम्बलडन में पांच सेटों के रोमांचक मुकाबले में हरा दिया जबकि महिला वर्ग में फ्रेंच ओपन फाइनलिस्ट जैस्मीन पाओलिनी ने उलटफेर भरी जीत के साथ पहली बार ग्रास कोर्ट के ग्रैंड स्लैम विम्बलडन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।

ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में 2-0 से आगे रहने के बाद पांच सेटों में पराजित पांचवीं वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में सिनर पर पांच सेटों के रोमांचक मुकाबले में 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 2-6, 6-3 से शानदार जीत दर्ज की।

मेदवेदेव ने 55 विनर लगाकर वर्ल्ड नंबर 1 को सीज़न की चौथी हार दी। अपनी चार घंटे की रोमांचक जीत के साथ, मेदवेदेव ने जोड़ी के करियर मुकाबले में 7-5 का सुधार किया। एटीपी टूर ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में मेदवेदेव के हवाले से कहा, मुझे पता था कि अगर मैं जानिक को हराऊंगा तो यह एक कठिन मैच होगा।वह ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसे आप आसानी से हरा सकें। एक समय वह बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था लेकिन उसने बेहतर खेलना शुरू कर दिया और मुझे खुशी है कि मैं उच्च स्तर पर बने रहने में कामयाब रहा। कुछ बेहतरीन अंक थे, यह एक शानदार मैच था और मैं जीत कर खुश हूं और मैं आगे देख रहा हूं।

अपने नौवें प्रमुख सेमीफाइनल (विंबलडन में लगातार दूसरे) में, एटीपी रैंकिंग में नंबर 5 खिलाड़ी 2021 यूएस ओपन के बाद अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब का पीछा कर रहा है। मेदवेदेव का सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त स्पैनियार्ड कार्लोस अल्काराज या 12वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी टॉमी पॉल से मुकाबला होगा।

उधर महिला वर्ग में फ्रेंच ओपन फाइनलिस्ट जैस्मीन पाओलिनी लगातार दूसरे बड़े फाइनल की राह पर बनी हुई हैं। वह एम्मा नवारो को हराकर विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इटली की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। पाओलिनी ने नंबर 19 वरीयता प्राप्त नवारो पर 6-2, 6-1 से शानदार जीत दर्ज की और पहली बार ग्रास-कोर्ट ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंची।

सेंटर कोर्ट पर पाओलिनी की 58 मिनट की जीत से पहले इतालवी महिलाएं विंबलडन में सभी चार क्वार्टर फाइनल हार गई थीं। क्रोएशिया की डोना वेकिच ने न्यूजीलैंड की क्वालीफायर लुलु सन को 5-7, 6-4, 6-1 से हराकर अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पिछड़ने के बाद जीत हासिल की।

अपने तीसरे ग्रैंड स्लैम क्वार्टरफाइनल में और विंबलडन में पहली बार, विश्व नंबर 37 वेकिच को 123वीं रैंकिंग वाली सुन को मात देने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसका लक्ष्य विंबलडन में महिला एकल सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए केवल दूसरा क्वालीफायर बनना था। 28 वर्षीय वेकिच ने अंततः नंबर 1 कोर्ट पर 2 घंटे और 8 मिनट के खेल के बाद 23 वर्षीय सन को पीछे छोड़ दिया।

न्यूज़ ब्रीफ

भारतीय फुटबॉल टीम के कोच बनने की दौड़ में शामिल रोजारियो और नौशाद

कोलकाता। भारतीय फुटबॉल टीम को अब आने वाले समय में नया कोच मिल सकता है। इगोर स्टिमक को कोच पद से हटाये जाने के बाद से ही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) नये कोच की तलाश कर रहा है। जिसके बाद उसे दुनिया भर से कई प्रस्ताव मिले हैं। इस पद के लिए मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व कोच स्टेनली रोजारियो और नॉर्थईस्ट यूनाईटेड के मौजूदा सहायक कोच नौशाद मूसा ने भी आवेदन किया है। इस पद के लिए 100 आवेदनकर्ता यूएफा प्रो लाइसेंस डिप्लोमा धारक हैं जबकि 20 के पास एएफसी प्रो लाइसेंस डिप्लोमा है। तीन के पास दक्षिण अमेरिका फुटबॉल परिसंघ (कोनमेबोल) लाइसेंस है। रोजारियो और मूसा एएफसी प्रो लाइसेंस डिप्लोमा धारक हैं। इसके अलावा मोहन बागान सुपर जाइंट्स को 2023-24 आईएसएल लीग शील्ड जिताने में सहायता करने वाले एंटोनियो लोपेज हबास ने भी आवेदन किया है। एक अधिकारी के अनुसार रोजारियो और मूसा उन भारतीयों में शामिल हैं जिन्होंने आवेदन किया है और वे एएफसी प्रो लाइसेंस धारक भी हैं। इसके अलावा एंटोनियो हबास ने भी आवेदन किया है। प्रस्तावों में शामिल भारतीय उम्मीदवारों के नाम 20 जुलाई को एआईएफएफ कार्यकारी समिति की बैठक में रखे जाएंगे। इससे पहले एआईएफएफ उपाध्यक्ष एनए हैरिस की अगुआई वाली समिति आवेदनों की समीक्षा करेगी। समिति में तकनीकी, लीग, प्रतियोगिता, वित्त और विकास समिति के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष भी शामिल होगा। एआईएफएफ ने कहा है कि इस महीने के अंत तक पुरुष टीम के नए कोच का नाम तय कर दिया जाएगा।

कोच के तौर पर बेहतर परिणाम देने के पूरे प्रयास करुंगा : गंभीर

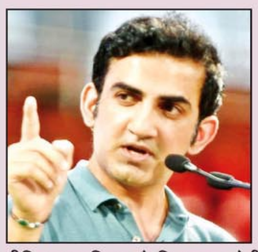

मुम्बई। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नये मुख्य कोच बने गौतम गंभीर ने कहा है कि वह टीम के लिए बेहतर परिणाम देने अपनी ओर से पूरे प्रयास करेंगे। गंभीर को राहुल द्रविड़ की जगह टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। गंभीर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत मेरी पहचान है और अपने देश की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। मैं टीम के साथ जुड़कर सम्मानित अनुभव कर रहा हूं, भले ही अब में खिलाड़ी की जगह पर कोच की भूमिका में हूं पर मेरा लक्ष्य हमेशा की तरह ही वही है, हर भारतीय को गर्व का अनुभव कराना है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम एक अरब 40 करोड़ लोगों की उम्मीदें लेकर चल रही है और मेरा प्रयास इसे पूरा करना रहेगा। गौरतलब है कि गंभीर काफी सख्त प्रकार के कोच माने जाते हैं। अब देखना होगा कि टीम के मुख्य कोच की भूमिका में वह कितने सफल होते हैं।

जेसविन और अंकिता अब पेरिस ओलंपिक में भाग लेंगे

नई दिल्ली। एथलीट जेसविन एल्ड्रिन और अंकिता ध्यानी अब पेरिस ओलंपिक में भाग लेते हुए नजर आयेंगे। जेसविन को पुरुषों की लंबी कूद और अंकिता को महिला वर्ग में पांच हजार मीटर दौड़ में विश्व रैंकिंग में जगह मिलने के साथ ही पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम में जगह मिल गयी है। इन दोनों एथलीटों के टीम में शामिल होने के साथ ही पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम के सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 30 पहुंच गयी है। विश्व एथलेटिक्स ने भी इन दोनो को शामिल किये जाने की पुष्टि की है। एल्ड्रिन को पुरुषों की लंबी कूद में 31 वां स्थान मिला है। उन्हें शीर्ष 32 एथलीटों में जगह मिलने के कारण ही पेरिस के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। दूसरी ओर महिलाओं की पांच हजार मीटर में अंकिता को 42 वां स्थान मिला, ये इस स्पर्धा में कटऑफ रैंक के अंदर है।

यूरो कप 2024 : फ्रांस को हराकर स्पेन यूरो कप 2024 के फाइनल में, 16 साल के स्पैनिश फुटबॉलर यमाल ने रचा इतिहास

बर्लिन।
यमाल ने बॉक्स के बाहर से शानदार स्ट्राइक कर गोल दागा और स्पेन को बराबरी करने में मदद की। गेंद फ्रांस के गोलकीपर माइक मैग्नन की अंगुलियों को छूते हुए गोलपोस्ट में चली गई।

16 वर्षीय लामेन यमाल यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे कम उम्र के गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। म्यूनिख में खेले गए सेमीफाइनल में यमाल और दानी ओल्मो की गोल की बदौलत स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हरा दिया और यूरो 2024 के फाइनल में जगह बनाई। रैंडल कोलो मुआनी के नौवें मिनट में किलियन एम्बाप्पे के क्रॉस पर किए गए गोल से पिछड़ते हुए स्पेन ने चार मिनट के अंदर ही मैच का पासा पलट दिया। स्पेन ने इस टूर्नामेंट में पिछले पांच मैचों में केवल एक गोल खाने वाली टीम के खिलाफ चार मिनट के अंदर दो गोल दागे और फिर से इस बढ़त को कायम रखते हुए जीत हासिल की। यमाल यूरो कप फाइनल से एक दिन पहले अपना 17वां जन्मदिन मनाएंगे। अब फाइनल में स्पेन का सामना बर्लिन में नीदरलैंड या इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।

यमाल ने बॉक्स के बाहर से शानदार स्ट्राइक कर गोल दागा और स्पेन को बराबरी करने में मदद की। गेंद फ्रांस के गोलकीपर माइक मैग्नन की अंगुलियों को छूते हुए गोलपोस्ट में चली गई। स्पेन ने 25वें मिनट में बढ़त बना ली जब दानी ओलमो ने नेट में गेंद को पहुंचा दिया। मिडफील्ड गेम मैनेजमेंट के मास्टर्स स्पेन ने बढ़त लेने के बाद डिफेंसिव खेल दिखाया। काउंटर अटैक के बजाय बॉल पजेशन पर ज्यादा ध्यान दिया।

तीन बार का चैंपियन स्पेन यूरो कप में छह मैच जीतने वाली पहला देश बन गया है और वह रिकॉर्ड चौथे खिताब से एक मैच दूर है। पिछले चार मेजर टूर्नामेंटों में से तीन में फाइनलिस्ट फ्रांस से जरूर सवाल पूछे जाएंगे कि वह कैसे आक्रामक फॉरवर्ड के बावजूद फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहा। कोच डिडिए डेशां ने एंटोनी ग्रीजमैन को तरजीह देने की बजाय ओस्मान डेम्बेले को लगातार मौका दिया। इसके अलावा जीरूड को भी बेंच पर बैठाए रखा। फिट नहीं होने के बावजूद एम्बाप्पे लगातार खेलते रहे।

यमाल का प्रदर्शन इस यूरो कप में शानदार रहा है। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में एक गोल के अलावा तीन असिस्ट भी किए हैं। वह इस प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे कम उम्र के स्कोरर हैं। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड डेढ़ साल के अंतर से तोड़ा।

चैंपियंस ट्रॉफी खेलने संन्यास से वापसी करने भी तैयार हैं वार्नर

सिडनी।
ऑस्ट्रेयिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए संन्यास से वापसी करने तैयार हैं। वार्नर ने कहा है कि वह इस एक आईसीसी टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार हैं। वार्नर ने टी20 विश्वकप के बाद इस प्रारुप से संन्यास की घोषणा कर दी थी।

चैंपियंस ट्रॉफी खेलने संन्यास से वापसी करने भी तैयार हैं वार्नर

इस खिलाड़ी ने प्रशंसकों और अपने साथियों के समर्थन के लिए उनका अभार जताया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलने की इच्छा जताया है। इस बल्लेबाज ने कहा कि मेरे करियर का समय अंतरराष्ट्रीय खेलने में लगा है। साथ ही कहा कि सभी प्रारूपों में 100 से अधिक खेलना मेरा सपना रहा है जिससे संभव बनाने में मुझे सभी का समर्थन मिलन और मैं उनके प्रति आभारी हूं। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी और मेरी बेटियां ने खेल के दौरान मेरा पूरा साथ दिया। जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। कोई भी बाहरी व्यक्ति कभी नहीं जान पाएगा कि हमने क्या-क्या सहा है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्रिकेट प्रशंसकों का मैंने अपने खेल से मनोरंजन किया है और टेस्ट क्रिकेट को तेजी से खेलकर बदलने का प्रयास किया है। साथ ही कहा कि हम प्रशंसकों के बिना वह नहीं कर सकते जो हमें पसंद है, इसलिए धन्यवाद। मैं कुछ समय तक फ्रैंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखूंगा और इसके बाद अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने को तैयार हूं। ऑस्ट्रेलिया की सीमित ओवरों की टीमें सितंबर में अपने सत्र की शुरुआत करेंगी। इसमें टीम पहली बार वार्नर के बिना ही उतरेगी। उसे सबसे पहले स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ तीन-तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है।

टेस्ट क्रिकेट शीर्ष टीमों के बीच ही खेला जाये टी20 के जरिये खेल को आगे बढ़ायें : शास्त्री

मुम्बई।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि टी20 से खेल को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिये। वहीं टेस्ट क्रिकेट केवल 6 या 7 देशों के बीच ही होना चाहिये। शास्त्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आप 2 स्तर रख सकते हैं पर टेस्ट क्रिकेट में रुचि बनाए रखने के लिए शीर्ष छह टीमों को ही खेलते रहने दें। आप इस खेल को टी20 जैसे अन्य प्रारूपों के जरिये दुनिया भर में लोकप्रिय बना सकते हैं पर इसके लिए खेल का स्तर अच्छा होना चाहिये क्योंकि अगर आपके पास गुणवत्ता नहीं है।

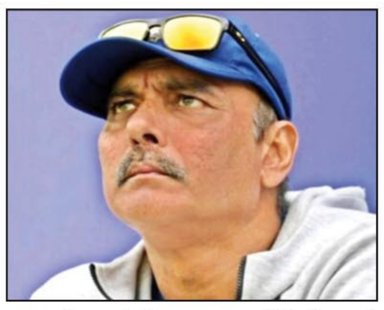

तो रेटिंग गिरती जाएगी। अगर आपके पास 12 टेस्ट मैच टीमें हैं तो इसे छह या सात तक ही सीमित करें। जो बढ़िया खेले ऊपर आए जो खराब खेले वह नीचे चली जाए और उससे आगे खेलने का अवसर नहीं मिले।

वहीं एमसीसी अध्यक्ष मार्क निकोलस ने कहा कि टी20 क्रिकेट से आने वाला पैसा खेल को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका हो सकता है। टी20 क्रिकेट ऐसा प्रारुप है जो हर कोई चाहता है। यह वह जगह है जहां नया बाजार है, जहां प्रशंसक हैं और जहां पैसा है। क्रिकेट में पैसे के आने को बाजारीकरण नाम दिया जा रहा है पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह खेल को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ के यादगार टेस्ट डेब्यू का हवाला देते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि युवाओं पर इसके प्रभाव के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को संरक्षित किया जाए।

मेसी ने दागा 109वां गोल, कनाडा को हराकर अर्जेंटीना कोपा अमेरिका के फाइनल में

ईस्ट रदरफोर्ड (न्यू जर्सी)।
अर्जेंटीना की तरफ से जूलियन अल्वारेज ने 22वें मिनट में पहला गोल किया जबकि मेसी ने 51वें मिनट में एन्जो फर्नांडीज के शॉट को गोल में भेज कर उसकी बढ़त दोगुनी की।

लियोनेल मेसी के अपने करियर के 109वें अंतरराष्ट्रीय गोल और वर्तमान टूर्नामेंट के पहले गोल के दम पर गत चैंपियन अर्जेंटीना ने कनाडा को 2-0 से हराकर कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया।

अर्जेंटीना की तरफ से जूलियन अल्वारेज ने 22वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि मेसी ने 51वें मिनट में एन्जो फर्नांडीज के शॉट को गोल में भेज कर उसकी बढ़त दोगुनी की। मेसी के सामने तब गोलकीपर मैक्सिम क्रेप्यू थे लेकिन इस स्टार फुटबॉलर के आगे उनकी एक नहीं चली।

मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपने पिछले 25 मैचों में 28 गोल किए हैं। वह कोपा अमेरिका में अब तक 14 गोल कर चुके हैं जो रिकॉर्ड से तीन गोल कम हैं। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में मेसी से अधिक गोल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर दर्ज हैं जिन्होंने अभी तक 130 गोल किए हैं। ईरान के अल देई के नाम 1993 से 2006 तक 108 या 109 गोल दर्ज हैं। इक्वाडोर के खिलाफ 2000 में किए गए उनके गोल को लेकर विवाद है क्योंकि इस मैच के अंतरराष्ट्रीय दर्जे को लेकर मतभेद हैं।

अर्जेंटीना ने यह जीत अपने स्वतंत्रता दिवस पर हासिल की जिससे उसका अजेय अभियान 10 मैच तक पहुंच गया है। अर्जेंटीना होने वाले फाइनल में उरुग्वे या कोलंबिया का सामना करके रिकॉर्ड 16वां कोपा खिताब जीतने की कोशिश करेगा।

ईशान ने बताया घरेलू क्रिकेट नहीं खेलने का कारण

मुम्बई।
पिछले साल हुए दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद से ही भारतीय टीम से बाहर चल रहे युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अब रणजी ट्रॉफी के अलावा घरेलू क्रिकेट नहीं खेलने का कारण बताया है। ईशान ने कहा, तब मैंने क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला लिया था। इसलिए मुझे लगा कि यह सामान्य बात है।

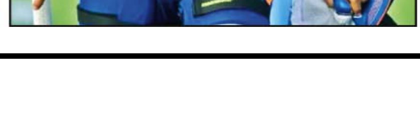

क्रिकेट बोर्ड का भी नियम है कि अगर कोई खिलाड़ी टीम में वापसी करना चाहता है तो उसे घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने साथ ही कहा, यह मेरे लिए इतना आसान भी नहीं था। इसका कारण है कि तब मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को छोड़कर ब्रेक लेने जा रहा था। ऐसे में कोई कैसे घरेलू क्रिकेट खेल सकता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक लेकर घरेलू क्रिकेट में मैच खेलने की बातअजीब है। इससे तो अच्छा ये होता कि मैं ब्रेक ही ना लेता और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ही खेलते रहता। ईशान ने आगे कहा, यह सारी बातें इतनी सहज नहीं थी, मेरे लिए बहुत ही निराशाजनक था। तब मैंने सोचा नहीं था कि हालात ऐसे होंगे। ईशान के घरेलू क्रिकेट नहीं खेलने के कारण बीसीसीसी नाराज था और उसने उसे केन्द्रीय अनुबंध भी नहीं दिया। इसके अलावा किसी भी सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं दी। ऐसे में ईशान के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों को अपने अपने राज्य की टीम की तरफ से घरेलू क्रिकेट में खेलने को कहा था। इसके बाद भी ईशान ना तो रणजी ट्रॉफी में खेलने उतरे और ना ही किसी और टूर्नामेंट में झारखंड की टीम के लिए खेलते नजर आए। इससे पहले ईशान ने एकदिवसीय में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था और उनका प्रदर्शन भी बेहतर होता जा रहा था। इसके बाद भी एक गलती के कारण वह टीम से बाहर हो गये।

द्रविड़ ने अतिरिक्त बोनस लेने से इंकार किया, बाकि कोचिंग स्टाफ जितनी राशि ही लेंगे

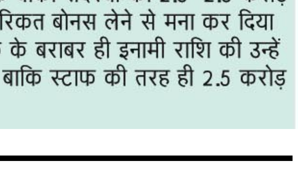

मुम्बई। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के मुख्य कोच रहे राहुल द्रविड़ सही मायनों में एक जेंटलमैन हैं। क्रिकेटर के अलावा मुख्य कोच के तौर पर भी वह अपने काम में पूरी तरह से समर्पित रहें हैं। अपनी सादगी और विनम्रता के लिए वह जाने जाते हैं। सफलता का श्रेय स्वयं न लेकर दूसरों को देना उनकी आदत रही है। अब मुख्य कोच पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने अपने व्यवहार से यही बात साबित की है। द्रविड़ ने कोच पद छोड़ते ही अतिरिक्त बोनस लेने से मना कर दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने टी20 विश्वकप विजेता टीम को 125 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। यह इनामी राशि खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के 42 सदस्यों के बीच बंटेगी। 125 करोड़ रुपए में से टीम के सभी 15 सदस्यों और कोच राहुल द्रविड़ को 5-5 करोड़ मिलने थे और कोचिंग स्टाफ के बाकी सदस्यों को 2.5-2.5 करोड़ रुपए मिलने थे। ऐसे में द्रविड़ ने अतिरिकत बोनस लेने से मना कर दिया है। द्रविड़ ने कहा है कि कोचिंग स्टाफ के बराबर ही इनामी राशि की उन्हें दी जाये। द्रविड़ का कहना है कि उन्हें बाकि स्टाफ की तरह ही 2.5 करोड़ रुपये ही दिये जाये।

प्रेग्नेंसी में पत्नी का कैसे रखें ख्याल

मां बनना एक बहुत ही सुखद एहसास है। लेकिन कोई भी महिला इस सुखद और सुंदर पहलू का आनंद तभी उठा सकती हैं जब गर्भावस्था के दौरान वो खुद और उसका बच्चा स्वस्थ रहे। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब गर्भवती महिला अपना अच्छे से ख्याल रखे। किन्तु गर्भावस्था के शुरू के तीन महीनों में कई महिलाओं को जी मचलाने या उल्टी आने की शिकायत होती है। इसके अतिरिक्त कुछ महिला उन दिनों बीमार भी पड़ जाती है। लेकिन होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है की उसकी माँ भी स्वस्थ रहे। इसलिए ऐसे में जरुरी है की पति अपनी पत्नी का ख्याल रखे। क्योंकि जब भी किसी लड़की को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है तो वह इस बात को सबसे पहले अपने पति के साथ शेयर करना चाहती है।

सबसे पहले खुद एडजस्ट करें

गर्भवती होने के बाद हर महिला के शरीर में काफी परिवर्तन आ जाता है जिसके चलते दैनिक कार्य रूटीन से नहीं हो पाते है। ऐसे में उन्हें कुछ भी कहने के बजाय कुछ समय के लिए आप खुद एडजस्ट करना सिख जाए ऐसे में आपकी पत्नी परेशान नहीं होगी। जितना हो सके आपको होने वाली मां के कम्फर्ट का ध्यान रखना है। यदि आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ दिन बाहर ही नाश्ता कर ले।

पत्नी को प्यार दे

गर्भवती होने के बाद अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को देखकर स्त्री बहुत परेशान रहती है। उन्हें ऐसा लगता है की वह गर्भावस्था के दौरान अच्छी नहीं दिखती हैं, अब उनके पति उन्हें प्यार नहीं करेंगे। इसलिए उनका भ्रम दूर करे। उन्हें हर पल जताए की आप उनसे प्यार करते है और वो पहले जितनी ही सुंदर हैं। इसके साथ ही उनका ख्याल भी रखें।

कुछ महत्वपूर्ण बातो का ध्यान रखे

पति कुछ जरुरी बातो की जानकारी रखें जैसे पत्नी को कब कौन सा इंजेक्शन लगना है या फिर चिकित्सक को कब दिखाना है आदि। इसके अतिरिक्त यदि आपकी पत्नी को किसी चीज से एलर्जी है तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा।

उसके खान पान का ख्याल रखे

देखा गया है की ज्यादातर महिलाएं इन दिनों में अपने खान-पान का विशेष ध्यान नहीं रख पातीं है। जिसे चलते उनके शरीर में लौह तत्व की कमी से एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपनी पत्नी के खान पान का भी ख्याल रखे। चाहे तो कुछ दिन के लिए अपने किसी रिस्तेदार को मदद के लिए बुलाले। गर्भावस्था में स्त्री को हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दाल, अंकुरित अनाज, प्रचुर मात्रा में दूध आदि अवश्य लेना चाहिए।

इन बातो का भी रखे ख्याल

- गर्भावस्था के दौरान अपनी पत्नी के साथ रेगुलर चेकअप पर जाएं। अल्ट्रासाउंड रूम में भी साथ रहें और बच्चे की हरकत को पेट छूकर महसूस करे।
- प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कमर में भयानक दर्द होता है। इसलिए ऐसे में उन पर अधिक काम का बोझ न लादें।
- अपनी पत्नी की भी बात सुनें, उनसे पूछें की उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। उनका ख्याल रखने के साथ साथ अधिकतर समय उनके साथ बिताएं।
- रोमेंटिक बातों के लिए टाइम निकाले, क्योंकि कुछ समय बाद आप दोनों अकेले नहीं रह जाएंगे। फिर शायद नन्हे को संभालने के चक्कर में आप एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए।

आफत न बन जाए आदत

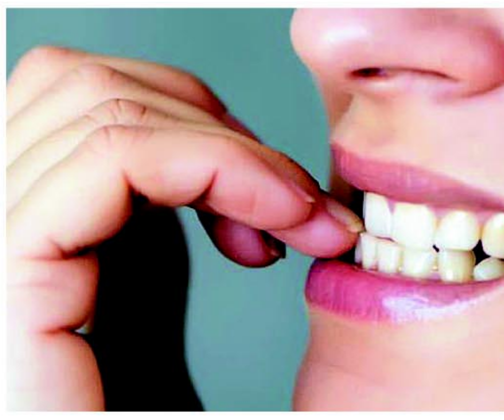

आदत से छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होता है। खासतौर पर ऐसी आदतें, जिनमें तनाव को कम करने का गुण होता है, पर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, उन्हें छोड़ना और भी मुश्किल होता है। धूम्रपान, तंबाकू और अत्यधिक शराब के सेवन को इनमें शामिल किया जाता है। पर उन आदतों का क्या, जो दिखने में तो सामान्य लगती हैं, पर सेहत पर गंभीर असर डालती हैं?

देर रात स्नैक्स खाना

देर रात कुछ खाने में इतनी बुराई नहीं है, पर फल-सब्जियों या हल्का खाने की बजाए ठंडा पिज्जा, ब्रेड स्लाइस, नूडल्स या तला-भुना खाना सेहत के लिए समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे लोग, जिन्हें एसिडिटी की समस्या रहती है, उनके लिए तो देर रात में खाना समस्या को बढ़ा सकता है।

क्या करें: आमतौर पर देर रात में खाना भूख की वजह से कम, बोरियत के कारण अधिक होता है। लोग टीवी या फिल्म देखते हुए आलू चिप्स या सैंडविच आदि खाते हैं। एक शोध के अनुसार, टीवी न देखते समय की तुलना में टीवी या फिल्म देखते समय लोग 44 प्रतिशत अधिक चिप्स खाते हैं। इस आदत से बचने के लिए बेहतर है कि आप टीवी देखते समय कुछ छोटे-छोटे काम कर लें, मसलन किए जाने वाले कार्यों की लिस्ट बनाना, कपड़ों की तह लगाना, ई-मेल चेक करना या अधूरे कामों को पूरा करना आदि। इससे आप कुछ खाने की अपनी इच्छा को दबा सकेंगे।

गलत फिटनेस एक्सेसरीज

यदि आप अपनी फिटनेस को लेकर सजग हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो अपनी फिटनेस एक्सेसरीज का भी अवश्य ध्यान रखें। गर्मी के दिनों में सामान्य सूती कमीज को पहन कर व्यायाम करना खुजली या त्वचा पर रगड़ उत्पन्न कर देता है। व्यायाम करते समय जूते-जुराब अवश्य पहनें।

क्या करें: सही स्पोर्ट शूज पहनें। ऐसी जगह से जूते खरीदें, जहां स्पोर्ट्स एक्सेसरीज मिलती हों। पसीने को सोखने वाले फेब्रिक से बने कपड़े पहनें। कपड़े आरामदेह या अधिक कसे हुए न हों।

भरपूर नींद न लेना

पर्याप्त नींद न लेना सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। इससे आपकी सक्रियता कम हो जाती है। पर्याप्त नींद की कमी रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम कर देती है। महिलाओं का पर्याप्त नींद न लेना हृदय रोगों की आशंका को बढ़ा देता है।

क्या करें: विशेषज्ञों के अनुसार, नींद आहार की तरह है। समय पर सोना चाहिए। सोने से पहले कैफीनयुक्त पदार्थों के सेवन से बचें। शोर और अतिरिक्त रोशनी से दूर रहें।

यदि आप रात को नहीं सो पा रहे हैं तो थोड़ी नींद दोपहर में लें। सोने से पहले टीवी व कंप्यूटर न देखें।

नाखून चबाना

नाखून चबाना एक सामान्य आदत है, जो अक्सर तब देखने को मिलती है, जब व्यक्ति तनाव में होता है। इससे नाखूनों की सामान्य वृद्धि पर तो असर पड़ता ही है, उनकी शेप भी अनियमित हो जाती है। नाखूनों की उचित सफाई न रखने पर उनमें जमा कीटाणु खाने के जरिए पेट में जाकर संक्रमण का कारण बन जाते हैं। नाखूनों की परत के नीचे नुकसानदायक स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया होता है, जो चबाने पर मुंह में चला जाता है। एक शोध के अनुसार, 19 से 29 प्रतिशत युवा वयस्क और 5 प्रतिशत बड़ी उम्र के व्यक्ति नाखून चबाते हैं।

क्या करें : दो से तीन सप्ताह में एक बार किसी प्रोफेशनल से मेनिक्योर करवा सकते हैं। जब आपके नाखून सुंदर लगते हैं तो आप उन्हें चबाना पसंद नहीं करते। नाखून चबाने की इच्छा उत्पन्न होने पर क्रीम या तेल से उनकी मालिश करें या फिर गाजर या सेब जैसी चीजें चबाएं।

डॉक्टर को पूरी बात न बताना

सेहत संबंधी समस्या है तो डॉक्टर के पास जाने से निश्चित तौर पर फायदा मिलता है, पर बातचीत करते समय चिकित्सक को पूरी बात न बताना उपचार के तरीके को बदल सकता है। खासतौर पर मधुमेह या हाइपरटेंशन से पीड़ितों के लिए दवा लेते समय विस्तृत बातचीत जरूरी है।

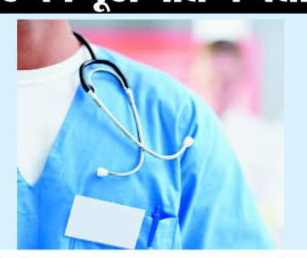

क्या करें: जब भी डॉक्टर के पास जाएं, बीमारी के लक्षणों और ली जा रही पूर्व दवाओं के बारे में पूरी जानकारी दें। बेहतर होगा कि मिलने से पहले पूरी सूची बना लें, जिसमें एल्कोहल या ली जा रही दवाओं व अन्य बातों की पूरी जानकारी दें।

कान में पिन डालना

कान में हल्का-सा भारीपन होने या फिर खुजली होने पर पहला ध्यान कान की सफाई करने का होता है। आमतौर पर लोग बालों में लगाने वाली पिन, बॉल पेन, पेंसिल आदि को कान में डाल कर कान के भीतर जमी परत को निकालते हैं, जिसे सामान्य शब्दों में मैल कह दिया जाता है।

क्या करें: कान में वेक्स जमा होने का एक बड़ा कारण भोजन को ढंग से चबा कर न खाना है। कान में लगाई जाने वाली एक्सेसरीज जैसे हैडफोन, लंबे समय तक ईयरफोन से भी वेक्स जमा होती है। इनसे बचें।

संगीत का रोग

प्रारंभ में भले ही आप कुछ देर हेडफोन लगा कर तेज आवाज में संगीत सुनते हैं, पर कुछ समय बाद आपके कान को उतनी ही आवाज में सुनने की आदत पड़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप तेज से तेज आवाज को ग्रहण करने लगे हैं। पर लंबे समय तक ऐसा करना आपके सुनने की क्षमता में स्थायी दोष उत्पन्न कर सकता है। आपको लगता है कि लगातार कान में कुछ आवाज हो रही है, जिसे टिनिटस कहा जाता है।

क्या करें: मस्तिष्क को धीमी आवाज सुनने के लिए तैयार करें। अपने आईपैड या कार स्टीरियो की आवाज धीमी रखें, इतनी कि दूसरे जो आपसे बात कर रहे हैं, उन्हें चिल्लाना न पड़े।

शाम स्क्रीन के साथ बिताना

सप्ताह में एक-दो बार काम के बाद थियेटर में फिल्म देखना या कुछ देर नियमित टीवी देखना सही हो सकता है, पर हर दिन देर रात तक स्क्रीन के सामने समय बिताना बुरी आदत है। जो लोग अत्यधिक तनाव में रहते हैं या जिनके दोस्तों का नेटवर्क सीमित है, वे अक्सर काम के बाद अकेले समय बिताते हैं। नतीजा देर तक सोफे पर बैठे-बैठे टीवी देखते रहने से शरीर और दिमाग थकता है। शोध कहता है कि सप्ताह में 19 घंटे से अधिक टीवी या बड़े परदे के आगे समय बिताना मोटापे की आशंका 97 प्रतिशत बढ़ा देता है।

क्या करें: विशेषज्ञों के अनुसार, इस आदत से छुटकारा पाने का तरीका है कि टीवी देखते समय कुछ काम करते रहें। सप्ताह में दो-तीन बार कुछ समय दोस्तों के साथ बिताएं। खेलकूद में समय दें।

प्यार करोगे तो मोटे हो जाओगे!

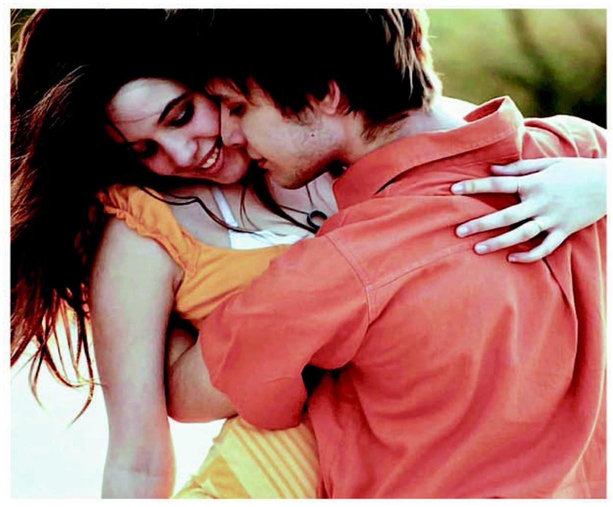

प्रेम होना किसी के लिए भी बेहद अमूल्य बात हो सकती है, लेकिन एक नए सर्वेक्षण के अनुसार मोटापा के लिए भी प्रेम में होना मुख्य कारण हो सकता है। नए सर्वेक्षण में प्रेम के कारण वजन बढ़ाने वाली कई परंपरागत परिस्थितियां बनती हैं, जैसे सहजता से भोजन करना, छुट्टियों में एक-दूसरे के साथ होना या व्यायाम न करना आदि।

सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि प्रेम होने के बाद उनका वजन बढ़ा। इन्हीं व्यक्तियों से ठीक तीन महीने बाद दोबारा पूछे जाने पर उन्होंने स्वीकार किया कि उनके प्रेमी युगल के वजन में भी इजाफा हुआ। सर्वेक्षण में शामिल दो तिहाई लोगों ने स्वीकार किया कि प्रेम होने के बाद उनके और उनके प्रेमी युगल के वजन में भी वृद्धि हुई।

महिलाओं ने स्वीकार

सर्वेक्षणकर्ता एवं डाइट शेफ की पोषण एवं वजन प्रबंधन विशेषज्ञ ने कहा कि सर्वेक्षण में कुछ बहुत रोचक परिणाम सामने आए हैं। यह जानना बहुत चौंकाने वाला है कि प्रेम होने के बाद लोग कितने आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं। सर्वेक्षण में शामिल अधिकतर महिलाओं ने स्वीकार किया कि जब वे अकेली थीं तब जितना भोजना करती थीं उसके मुकाबले साथी के साथ भोजन के दौरान वे थोड़ा ज्यादा भोजन करती हैं।

सर्वेक्षण में शामिल अधिकतर युगलों ने अपनी दिनचर्या में साथ-साथ टीवी देखना, घर में हों तब भी साथ-साथ भोजन करना और अगर बाहर हों तब भी साथ-साथ भोजन करना स्वीकार किया। इससे उनकी दैनिक क्रियाओं की गतिविधियों का पता चलता है।

फार्मा सेक्टर में बेहतर मौके...

फार्मेसी एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें मंदी के दौरान भी नौकरी की कोई कमी नहीं होती। करियर के लिहाज से देखें, तो यह एक शानदार सेक्टर है। मौजूदा समय में भारत क्लीनिकल रिसर्च आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भी ग्लोबल हब बन कर उभर रहा है। ऐसे में अगर आप चिकित्सा और सेहत के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं तो फार्मेसी में करियर बना कर अपने भविष्य को संवारने का बेहतर मौका मिल सकता है। साइंस विषय के साथ बारहवीं परीक्षा पास करने के बाद दो साल के डी फार्मा कोर्स या चार साल के बी फार्मा कोर्स कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित कई संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अंडरग्रेजुएट कोर्स करवाने के अलावा एम फार्मा कोर्स भी करवाते हैं। पहले भारत में फार्मास्युटिकल की पढ़ाई गिने-चुने संस्थानों में ही होती थी, लेकिन तेजी से बढ़ते बाजार और ट्रेंड लोगों की मांग को पूरा करने के लिए अब कई संस्थानों में ऐसे कोर्सेस की शुरुआत हो गई है। छात्र अब बारहवीं के बाद सीधे डिप्लोमा कर सकते हैं। कुछ कॉलेजों में फार्मेसी में फुलटाइम कोर्स संचालित हैं।

स्पेशलाइजेशन के लिए

फार्मा रिसर्च में स्पेशलाइजेशन के लिए एनआईपीईआर यानी नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। इसके साथ-साथ पीजी डिप्लोमा इन फार्मास्युटिकल एवं हेल्थ केयर मार्केटिंग, डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग, एडवांस डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग एवं पीजी डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग जैसे कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों की अवधि छह माह से एक वर्ष के बीच है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता बीएससी, बीफार्मा अथवा डीफार्मा निर्धारित की गई है।

व्यक्तिगत योग्यता

यदि आप फार्मेसी की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी साइंस और खासकर लाइफ साइंस तथा दवाइयों के प्रति दिलचस्पी होनी चाहिए। इससे जुड़े रिसर्च के क्षेत्र में काम करने के लिए आपकी दिमागी विश्लेषण क्षमता बेहतर हो और आपकी शैक्षणिक बुनियाद भी अच्छी होनी चाहिए। यदि आप इससे जुड़े मार्केटिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जरूर बेहतर होनी चाहिए। डीफॉर्मा और बीफॉर्मा कोर्स में दवा के क्षेत्र से जुड़ी उन सभी बातों की थ्योरेटिकल और प्रायोगिक जानकारी दी जाती है जिनका प्रयोग आमतौर पर इस उद्योग के लिए जरूरी होता है। इसके साथ फार्माकोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लीनिकल फार्मेसी, फॉर्मास्यूटिकल, हेल्थ एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी आदि विषयों की जानकारी दी जाती है।

रिसर्च एंड डेवलपमेंट

भारत आज फार्मास्युटिकल्स के क्षेत्र में काफी तेजी के आगे बढ़ रहा है। वैसे, इस क्षेत्र का दायरा भी काफी व्यापक है। यहां नई-नई दवाइयों की खोज व विकास संबंधी कार्य किया जा सकता है। आरएंडडी क्षेत्र को जेनेरिक उत्पादों के विकास, एनालिटिकल आरएंडडी, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट्स या बल्क ड्रग आरएंडडी जैसी श्रेणियों में बांटा जा सकता हैं। इन सबका अपना सुपर-स्पेशलाइजेशन है।

कुछ प्रमुख संस्थान

- नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फॉर्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पंजाब
- आचार्या एंड बीएम रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मासी, बंगलुरु
- कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, दिल्ली विश्वविद्यालय
- गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा
- बांबे कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, मुंबई
- गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, केरल
- बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पिलानी
- बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
- राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, बेंगलुरु
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़

ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर

यह इस इंडस्ट्री की एक बेहद अहम शाखा है, जो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराती है। आप चाहें, तो इस क्षेत्र में मॉलिक्युलर बॉयोलॉजिस्ट, फार्मेकोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट या मेडिकल इंवेस्टिगेटर बनकर अपना भविष्य संवार सकते हैं। मॉलिक्युलर बॉयोलॉजिस्ट जीन संरचना के अध्ययन और मेडिकल व ड्रग रिसर्च संबंधी मामलों में प्रोटीन के इस्तेमाल का अध्ययन करता है, जबकि फार्मेकोलॉजिस्ट का काम इंसान के अंगों व ऊतकों पर दवाइयों व अन्य पर्दाथों के प्रभाव का अध्ययन करना होता है। इसी तरह टॉक्सिकोलॉजिस्ट दवाओं के घातक प्रभाव को मापने के लिए अलग-अलग परीक्षण करता है।

मेडिकल इंवेस्टिगेटर

नई दवाइयों के विकास व टेस्टिंग की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। मानव जैविकी और दवाइयों संबंधी अपने बैकग्राउंड के कारण वे इसकी रिसर्च प्रक्रिया के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। हॉस्पिटल पर दवाइयों और चिकित्सा संबंधी अन्य सहायक सामग्रियों के भंडारण, स्टॉकिंग और वितरण का जिम्मा होता है, जबकि रिटेल सेक्टर में फार्मासिस्ट को एक बिजनेस मैनेजर की तरह काम करते हुए दवा संबंधी कारोबार चलाने में समर्थ होना चाहिए।

क्लिनिकल रिसर्च

जब कोई नई दवा लॉन्च करने की तैयारी होती है, तो दवा लोगों के लिए कितनी सुरक्षित और असरदार है, इसके लिए क्लिनिकल ट्रॉयल होता है। भारत की जनसंख्या और यहां उपलब्ध सस्ते प्रोफेशनल की वजह से क्लिनिकल का कारोबार तेजी से फलने-फूलने लगा है। इस क्षेत्र में हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय जगत की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। आज देश में कई विदेशी कंपनियां क्लिनिकल रिसर्च के लिए आ रही हैं। दवाइयों की स्क्रीनिंग संबंधी काम में नई दवाओं या फॉर्मुलेशन का पशु मॉडलों पर परीक्षण करना या क्लिनिकल रिसर्च करना शामिल है जो इंसानी परीक्षण के लिए जरूरी है।

क्वालिटी कंट्रोल

फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री का यह एक अहम कार्य है। नई दवाओं के संबंध में अनुसंधान व विकास के अलावा यह सुनिश्चित करने की भी जरूरत होती है कि इन दवाइयों के जो नतीजे बताए जा रहे हैं, वे सुरक्षित, स्थायी और आशा के अनुरूप हैं।

रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट

जिस तरह डॉक्टरों को प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, उसी तरह इन्हें भी फार्मेसी में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस चाहिए। उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए एक टेस्ट पास करना होता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस विषय में ट्रेनिंग के लिए 'फार्मा डी' नामक एक छह साल का कोर्स शुरू किया है।

ब्रांडिंग एंड सेल्स

फार्मेसी की पृष्ठभूमि से जुड़ा कोई प्रोफेशनल, एमबीए डिग्रीधारी और यहां तक कि साइंस की डिग्री प्राप्त करने वाला शख्स भी सेल्स एंड मार्केटिंग में करियर बना सकता है। फार्मास्युटिकल सेक्टर में मार्केटिंग की काफी अहम है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स उत्पाद की बिक्री के अलावा बाजार की प्रतिस्पर्धा पर भी निगाह रखते हुए इस बात का निर्धारण करते हैं कि किस उत्पाद के लिए बाजार में ज्यादा संभावनाएं हैं। इसी के मुताबिक रणनीति तैयार की जाती है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए यदि आपके पास बीफार्मा के साथ साथ एमबीए की भी डिग्री है तो सोने पर सुहागा वाली बात होगी। प्रशिक्षित पेशेवर की मांग दुनिया की बेहतरीन फॉर्मास्यूटिकल कंपनियां भारत में अपना कारोबार कर रही हैं। इनके अलावा, रैनबैक्सी, एफडीसी, कैडिला, शिपला, डॉ. रेड्डीज, डाबर, ल्यूपिन आदि कंपनियां भारत में व्यवसायरत हैं। इस क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की काफी मांग है।

यहां हैं मौके

नर्सिंग होम, अस्पतालों और कंपनियों में आपके लिए नौकरी के अवसर हैं। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्म्ड फोर्सेज में भी काफी संभावनाएं हैं। बीफॉर्मा करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, एनालिस्ट कैमिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्लीनिकल रिसर्च आउटसोर्सिंग सेक्टर में भी आपके लिए कई अवसर मौजूद हैं। जिस तरह से मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है और दवाइयों की खपत बढ़ीं हैं।

जेरियाट्रिक्स केयर बन कर सकते हैं चाहत पूरी

अगर आप सेवा के जुड़े क्षेत्र में कॅरियर बनाना चाहते हैं और साथ में अच्छी कमाई भी करना चाहते हैं कि जेरियाट्रिक्स केयर बन अपनी चाहत पूरी कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय करता है। इसका मकसद युवक-युवतियों को बुजर्गों की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना है। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। दरअसल बुजर्गों की सेवा के लिए इस क्षेत्र में दक्ष लोगों की जरूरत को काफी पहले से महसूस किया जा रहा था।

इस जरूरत को ध्यान में रखकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने जेरियाट्रिक्स केयर पाठ्यक्रम की शुरुआत की जिसके तहत बुजुर्गों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया जाता है। इस पाठ्यक्रम में मूल रूप से विद्यार्थियों को समुदाय के अंदर वृद्ध लोगों की स्थित, एकल और संयुक्त परिवारों के गुण-दोष, सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय, वृद्धावस्था में मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिति को समझने, पुनर्वास के अलावा उनकी समस्याओं को निपटाना, उनकी पोषाहार संबंधी जरूरतों की जानकारी और आहार प्रबंधन और मनोविज्ञान के अलावा वृद्धावस्था संबंधी देखभाल के आधारभूत सिद्धांतों की जानकारी दी जाती है। इस पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को घर-घर जाकर वृद्धों की समस्याओं पर रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है।

अपार संभावनाएं

इस क्षेत्र में हाल के दिनों में अपार संभावनाएं उभरी हैं। पीजी डिप्लोमाधारी अभ्यार्थी किसी सरकारी, गैर सरकारी, कॉरपोरेट क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थाओं में अच्छे पद पर कार्य कर सकता है। इसके अलावा गृह देखभाल कर्ता, उपचार सहायक, शारीरिक चिकित्सा सहायक, परियोजना निदेशक, कार्यक्रम अधिकारी, कल्याण अधिकारी बनकर भविष्य संवार सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

- डॉ. रेड्डी हैरिटेज फाउंडेशन, हैदराबाद।
- कलकत्ता मैट्रोपोलिटेन इंस्टीट्यूट ऑफ जिरानहोलॉजी, कोलकाता।
- न्यू इंटिग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी, इम्फाल।
- राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, आरके पुरम, नई दिल्ली।

तीन कोर्स

बुजुर्गों की देखभाल संबंधी प्रमुख तौर पर तीन कोर्स चलाए जाते हैं। जिसमें तीन महीने और 6 महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और पीजी डिप्लोमा कोर्स शामिल है। तीन माह का कोर्स खासतौर से समाजसेवी संस्थाओं के लिए है जो देश में बुजुर्गों की देखभाल और उनके लिए कार्य करती हैं। पीजी डिप्लोमा कोर्स का मुख्य उद्देश्य समर्पित व्यक्तियों की एक टीम तैयार करना होता है। पीजी डिप्लोमा कोर्स में इस क्षेत्र से संबंधित गहन अध्ययन कराया जाता है जिसमें थ्योरी स्तर प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य के अलावा इंटर्निशप और सेमिनार प्रस्तुति भी सिखाई जाती है।

ऐसे होता है दाखिला

इन सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा देना पड़ती है। पीजी डिप्लोमा कोर्स में नामांकन के लिए उम्मीदावार को किसी भी संस्थान से समाज विज्ञान, समाज कार्य, मानव विज्ञान, परिचर्चा या गृहविज्ञान में स्नातक होना आवश्यक है। साथ ही अभ्यर्थी की उम्र किसी भी हालत में 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए।

वहीं वृद्धावस्था देखभाल संगठनों में कार्यरत या वृद्धावस्था सेवा क्षेत्र में प्रमाणपत्र प्राप्त उम्मीदवारों, सामाजिक कार्यकर्ता, काउंसलर, स्वास्थ्य कर्मी और नर्सिंग के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

जबकि 3 और 6 महीने के प्रमाणपत्र कोर्स के लिए उम्मीदवार का मैट्रिक पास होना आवश्यक है साथ ही उसकी आयु 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को साक्षात्कार से भी गुजरना पड़ता है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : डॉ. आसमां बेगम ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**